बच्चे कहां हैं?

बिहार में सरकारी स्कूलों का अजीब मामला

जन जागरण शक्ति संगठन

जुलाई 2023

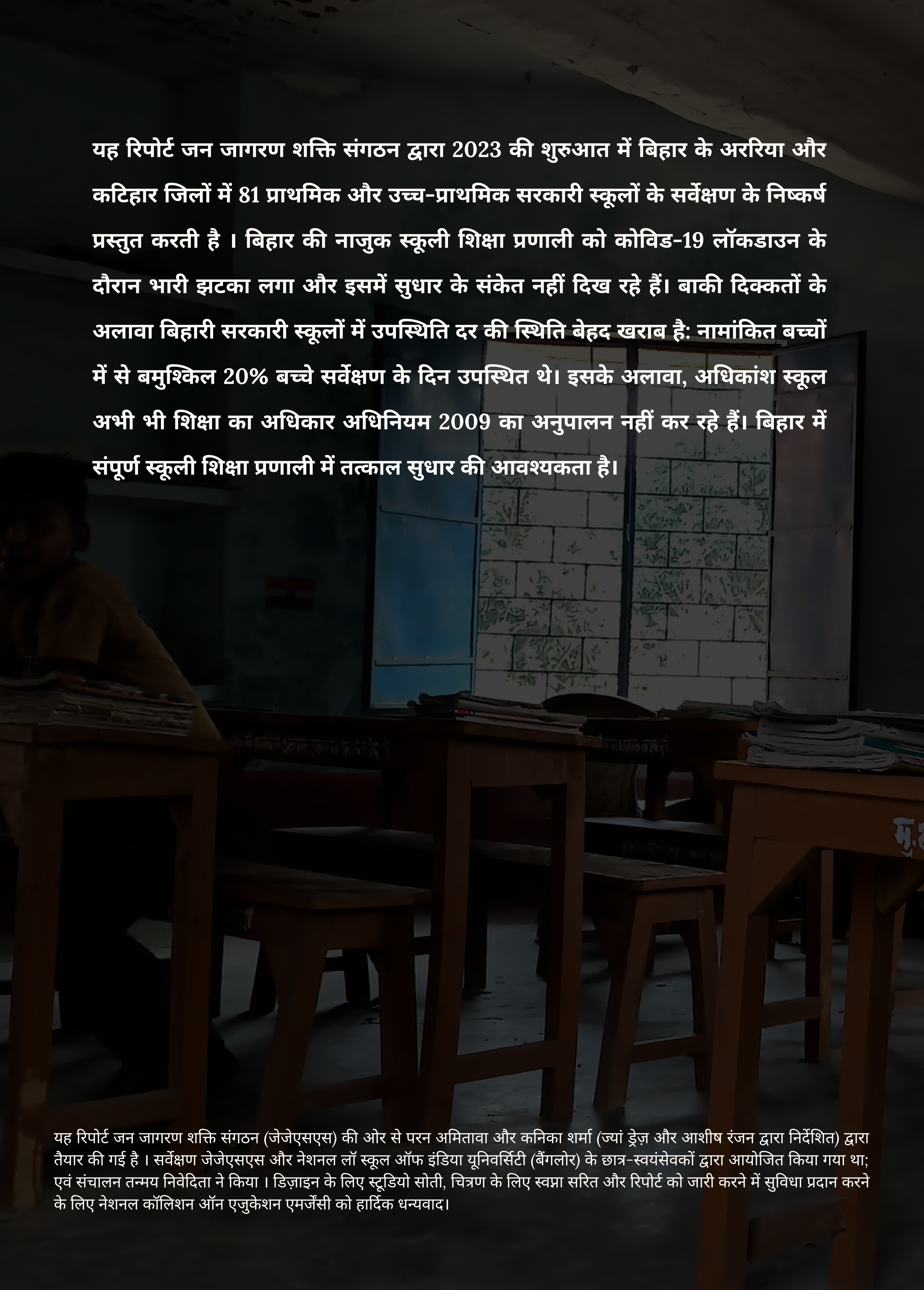

यह रिपोर्ट जन जागरण शक्ति संगठन द्वारा 2023 की शुरुआत में बिहार के अररिया और कटिहार जिलों में 81 प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक सरकारी स्कूलों के सर्वेक्षण के निष्कर्ष प्रस्तुत करती है । बिहार की नाजुक स्कूली शिक्षा प्रणाली को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भारी झटका लगा और इसमें सुधार के संकेत नहीं दिख रहे हैं। बाकी दिक्कतों के अलावा बिहारी सरकारी स्कूलों में उपस्थिति दर की स्थिति बेहद खराब है: नामांकित बच्चों में से बमुश्किल 20% बच्चे सर्वेक्षण के दिन उपस्थित थे। इसके अलावा, अधिकांश स्कूल अभी भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। बिहार में संपूर्ण स्कूली शिक्षा प्रणाली में तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

यह रिपोर्ट जन जागरण शक्ति संगठन (जेजेएसएस) की ओर से परन अमितावा और कनिका शर्मा (ज्यां ड्रेज़ और आशीष रंजन द्वारा निर्देशित) द्वारा तैयार की गई है । सर्वेक्षण जेजेएसएस और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (बैंगलोर) के छात्र-स्वयंसेवकों द्वारा आयोजित किया गया था; एवं संचालन तन्मय निवेदिता ने किया । डिज़ाइन के लिए स्टूडियो सोती, चित्रण के लिए स्वप्ना सरित और रिपोर्ट को जारी करने में सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल कॉलिशन ऑन एजुकेशन एमर्जेंसी को हार्दिक धन्यवाद।

सर्वेक्षण की मुख्य बातें

बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. सैंपल के दो-तिहाई प्राथमिक विद्यालयों और लगभग सभी उच्च-प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात 30 से ऊपर है (शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र-शिक्षक अनुपात अधिकतम 30 होना चाहिए)

विद्यार्थियों की उपस्थिति बेहद कम है. प्राथमिक विद्यालयों में, नामांकित बच्चों में से केवल 23% बच्चे सर्वेक्षण के समय उपस्थित थे। उच्च-प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और भी कम थी - केवल 20%।

शिक्षक नियमित रूप से स्कूल रजिस्टरों में उपस्थिति के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन बढ़े हुए आंकड़े भी बहुत कम हैं: प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः 44% और 40%।

कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से बड़े पैमाने पर पढ़ाई का नुकसान हुआ। आधे स्कूलों ने बताया कि कक्षा 3-5 के अधिकांश छात्र स्कूल दोबारा खुलने तक पढ़ना-लिखना भूल गए थे।

इन नुकसानों और बच्चों की शिक्षा और भलाई पर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के अन्य प्रतिकूल प्रभावों की भरपाई के लिए बहुत कम काम किया गया है।

स्कूलों में निराशाजनक बुनियादी ढांचे और सुविधाएं हैं, खासकर प्राथमिक स्तर पर। अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों (90%) में कोई उचित चारदीवारी, खेल का मैदान या पुस्तकालय नहीं है।

कुछ स्कूलों (सर्वेक्षण में चयनित सभी स्कूलों का 9%) के पास भवन तक नहीं है।

20 % स्कूलों के अनुसार मध्याह्न भोजन (एमडीएम) का बजट अपर्याप्त था। एमडीएम से संबंधित कई मुद्दे सामने आए: अत्यधिक काम का बोझ; अंडे के लिए कम बजट; एकाधिक खाना पकाने की व्यवस्था; और अंडे का ब्राह्मणवादी विरोध।

पाठ्यपुस्तकों और वर्दी के लिए बिहार की तथाकथित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणाली विफल है। अधिकांश स्कूलों में, कई छात्रों के पास कोई पाठ्यपुस्तकें या पोशाक नहीं है, या तो क्योंकि उन्हें डीबीटी राशि नहीं मिली या उन्होंने इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया।

निजी कोचिंग सेंटर द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार के सरकारी स्कूलों की जगह लेने का ख़तरा मंडरा रहा है |

उत्तर बिहार में स्कूली शिक्षा आपातकाल

स्कूली शिक्षा के महत्व को शायद ही कम करके आंका जा सकता है। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण ताकत प्रदान कर सकती है, लेकिन बिहार की स्कूली शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। पहले के साक्ष्यों से पता चलता है कि बिहार के स्कूल सभी संकेतकों में खराब प्रदर्शन करते हैं और गलत जानकारी के आधार पर बनी शिक्षा नीतियों द्वारा निर्मित संकट से जूझ रहे हैं। वे लगातार शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, और शिक्षकों, पाठ्यपुस्तकों, वर्दी, बुनियादी ढांचे और सार्थक सीखने के माहौल की गंभीर कमी प्रदर्शित करते हैं। 2014 में, बिहार सरकार और एएसईआर के संयुक्त मूल्यांकन में पाया गया कि ग्रेड IV में केवल 40% छात्र और ग्रेड VI में 60% छात्र ग्रेड II स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अधिकांश बच्चे जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे एकीकृत करने, निष्कर्ष निकालने या सारांशित करने में असमर्थ थे (ASER, 2014).

कोविड-19 महामारी और उसके साथ लगे लॉकडाउन ने बिहार की स्कूली शिक्षा प्रणाली को बुरी तरह प्रभावित किया । स्कूल लगभग दो वर्षों तक बंद रहे, जिससे बच्चों की शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई और साथ ही स्कूल के बुनियादी ढांचे या कार्य संस्कृति में कोई भी प्रगति रुक गई। विशेष सुविधा प्राप्त बच्चे ऑनलाइन या निजी ट्यूशन के माध्यम से अध्ययन करने में सक्षम थे, पर उनकी संख्यां बहुत कम थी. अधिकाँश बच्चों को उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया था। इसके कारण शैक्षिक अवसरों में मौजूदा असमानतायें और बढ़ गयीं । पड़ोसी राज्य झारखंड के चिंताजनक साक्ष्य से पता चलता है कि कई बच्चे वह भूल गए जो उन्होंने कोविड महामारी से पहले सीखा था, और उन्हें वापिस उस स्तर पर लाने के लिए कोई गंभीर उपाय नहीं किए गए हैं (ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड, 2022) ।

उत्तर बिहार में स्कूली शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है? इसे समझने के लिए, जन जागरण शक्ति संगठन ने जनवरी-फरवरी 2023 में कटिहार और अररिया जिलों में प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक विद्यालयों का एक सर्वेक्षण किया। यह रिपोर्ट सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष प्रस्तुत करती है।

जेजेएसएस सर्वेक्षण

यह सर्वेक्षण सरकारी प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक विद्यालयों में आयोजित किया गया था, जिनमें सामाजिक रूप से वंचित समूहों (एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम) के कम से कम 50% छात्रों का नामांकन था। यह सर्वे अररिया और कटिहार जिलों के 11 ब्लॉकों में किया गया । प्रत्येक ब्लॉक में, हमने बिना किसी क्रम के चयनित[1] 10 स्कूलों (5 प्राथमिक और 5 उच्च-प्राथमिक) की एक "टार्गेट" सूची बनाई। समय की कमी के कारण सैंपल के सभी स्कूलों को कवर नहीं किया जा सका। कुल 81 स्कूलों (40 प्राथमिक और 41 उच्च-प्राथमिक) का सर्वेक्षण किया गया। हालाँकि यह सैंपल बिहार के सभी सरकारी स्कूलों का प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन यह उत्तर बिहार में वंचित बच्चों के लिए सुलभ स्कूलों का काफी हद तक प्रतिनिधित्व करता है ।

"टारगेट" स्कूल का पता लगाने के बाद, सर्वेक्षण टीम (जेजेएसएस और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर के छात्र-स्वयंसेवक) बिना किसी पूर्व घोषणा के आधिकारिक स्कूल समय के दौरान स्कूल पहुंच गयी । ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि जहां तक संभव हो स्कूलों का सर्वेक्षण किया जाए और उन्हें उनकी सामान्य स्थिति में देखा जाए। डेटा संग्रह की तीन पूरक विधियों का उपयोग किया गया। सबसे पहले, टीम ने स्कूल के सबसे वरिष्ठ शिक्षक (अब से "प्रतिवादी शिक्षक") के साथ एक संरचित साक्षात्कार आयोजित किया। प्रश्नावली में बुनियादी ढांचे, शिक्षण विधियों, कोविड के बाद के उपचारात्मक उपायों, मध्याह्न भोजन और स्कूल में सुधार से संबंधित चुनौतियों और राय से संबंधित विषयों को शामिल किया गया। दूसरा, टीम ने नामांकन और उपस्थिति रजिस्टर जैसे स्कूल रिकॉर्ड की जांच की। तीसरा, टीम ने स्कूल, उसके छात्रों और आसपास के संदर्भ के बारे में अपनी टिप्पणियाँ दर्ज कीं। ये पूरक विधियाँ उत्तरी बिहार में स्कूली शिक्षा को विभिन्न रूप से देखने में मदद करती हैं। सर्वेक्षण टीमों ने कभी-कभी माता-पिता या बच्चों के साथ भी चर्चा की, लेकिन उनके साथ औपचारिक साक्षात्कार आयोजित करने के लिए समय और संसाधन बहुत कम थे।

[1] बिहार में उच्च-प्राथमिक विद्यालयों को बोलचाल की भाषा में मध्य विद्यालय कहा जाता है।

अपर्याप्त, अप्रभावी और उदासीन

सर्वेक्षण से उत्तर बिहार में स्कूली शिक्षा के "न्यूनतम मानदंड" सुनिश्चित करने में गंभीर विफलता का पता चलता है। इन स्कूलों को जिन मुद्दों का सामना करना पड़ता है, उन्हें तीन अलग-अलग लेकिन अन्योन्याश्रित विफलताओं के प्रतिबिंब के रूप में देखा जा सकता है: अपर्याप्त संसाधन; अप्रभावी नीतियां; और उदासीन कार्रवाई. कोविड-19 महामारी ने न केवल इन मुद्दों को बढ़ाया बल्कि नए मुद्दे भी जोड़े। हम नीचे इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले, हम एक केस स्टडी प्रस्तुत करते हैं जो उत्तर बिहार के उत्तर बिहार के वंचित क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में क्या दिक्कतें हैं, इसकी एक झलक देती है।

उत्तर बिहार का एक वंचित सरकारी स्कूल

प्राथमिक विद्यालय संथाली टोला (लाहटोरा, अररिया) तक सड़क मार्ग नहीं था, और खेतों को पार करके वहां तक पहुंचना पड़ता था। पहली नजर में हमने देखा कि स्कूल भवन कितना जर्जर था। यह स्कूल मुख्यतः संथालों के एक गाँव के लिए था, जो ऐसी अनुसूचित जनजाति है जिसकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियाँ अत्यधिक अभाव और हाशिए पर हैं। इस विद्यालय में मात्र दो शिक्षक कार्यरत थे. जब की दोनों उपस्थित थे, तब भी उचित अर्थों में कोई कक्षा नहीं लग रही थी। सभी बच्चों को गलियारे में पतली बोरियों पर बिठाया गया था, जो बमुश्किल उन्हें ठंड से बचाती दिख रही थीं। कक्षाओं में शायद ही कोई बेंच और कुर्सियाँ थीं। हमें बताया गया कि वहां एकमात्र उपयोग योग्य फर्नीचर शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से खरीदा गया था।

स्कूल के कामकाज की सेवा में खर्च करना केवल फर्नीचर तक ही सीमित नहीं था। शिक्षकों ने अपने साक्षात्कार में यह भी बताया कि उन्हें मध्याह्न भोजन की शेष राशि अपनी जेब से भरनी पड़ी क्योंकि उन्हें जो धनराशि दी गई थी वह अपर्याप्त थी। इस स्कूल का खाना पकाने का शेड भी बहुत खराब स्थिति में था और पिछले बरसात के मौसम में इसकी छत उड़ गई थी, जिससे स्वच्छता की समस्या पैदा हो गई थी।

हमें कई छात्र यूनिफॉर्म में नहीं दिखे. शिक्षकों का कहना है कि इसका मुख्य कारण यह है कि अभिभावकों के खाते में भेजी जाने वाली वर्दी की धनराशि अक्सर अन्य कार्यों में खर्च हो जाती है। यही बात पाठ्यपुस्तकों को खरीदने के लिए आवंटित धन पर भी लागू होती है - अधिकांश के पास पुस्तकें नहीं थीं। पाठ्यपुस्तकों की कमी एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि स्कूलों में शिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार हो और वंचित समुदायों के छात्र शैक्षणिक रूप से पीछे न रहें।

शायद इस स्कूल की सबसे अधिक ध्यानआकर्षित करने वाली बात स्कूल तक पहुचने का खराब रास्ता था । हमें स्थानीय लोगों और शिक्षकों ने बताया कि बरसात के मौसम में, कोई केवल नाव से ही स्कूल पहुंच सकता था और कक्षाएं छत पर लगानी पड़ती थीं क्योंकि नीचे सब कुछ पानी में डूबा हुआ था। किसी को आश्चर्य होता है कि ऐसे माहौल में सीखने में कोई आनंद कैसे हो सकता है।

शशांक सिन्हा, छात्र स्वयंसेवक (एन एल एस आई यू बैंगलोर)

शिक्षकों की कमी

बिहार भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है। एक किलोमीटर के दायरे (आरटीई अधिनियम के तहत किसी बस्ती से निकटतम स्कूल की अधिकतम दूरी) के भीतर बच्चों की संख्या अक्सर काफी बड़ी होती है। शायद यही कारण है कि बिहार में प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होती है। हमारे सैंपल में, प्राथमिक विद्यालयों में औसतन 147 छात्र थे, और उच्च-प्राथमिक विद्यालयों में 488 छात्र थे। शिक्षकों की संख्या इन उच्च नामांकन आंकड़ों से मेल खाने में विफल रही: प्राथमिक विद्यालयों में औसतन 4 शिक्षक, और उच्च-प्राथमिक विद्यालयों में 8 (तालिका 1)। ऐसा लग सकता है कि 4 शिक्षक एक प्राथमिक विद्यालय को अच्छी तरह से चलाने में सक्षम होंगे, प्रत्येक कक्षा में लगभग एक शिक्षक और कुछ ग्रेड को एक ही कक्षा में बैठाया जाएगा (बहु-कक्षा शिक्षण)। वास्तविकता यह है कि जब प्राथमिक विद्यालयों में 5 से कम शिक्षक होते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि एक कक्षा में कोई शिक्षक नहीं है।

तालिका 1: सैंपल विद्यालय

	प्राथमिक विद्यालय	**उच्च-प्राथमिक विद्यालय**
सैंपल विद्यालयों की संख्या	40	41
नामांकित बच्चों की औसत संख्या	147	488
कक्षाओं की औसत संख्या	4	9
शिक्षकों की औसत संख्या	4	8
औसत छात्र/शिक्षक अनुपात	43	57

नोट: प्राथमिक विद्यालय = कक्षा 1-5. उच्च-प्राथमिक विद्यालय = कक्षा 1-8.

कुल मिलाकर, सर्वेक्षण में सैंपल स्कूलों में उच्च छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) पाया गया है। आरटीई अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। जेजेएसएस सर्वेक्षण से पता चलता है कि 95% उच्च-प्राथमिक विद्यालयों और 65% प्राथमिक विद्यालयों में पीटीआर 30 से ऊपर है, जिससे यह सरल लेकिन महत्वपूर्ण आरटीई मानदंड टूट गया है। जैसा कि तालिका 2 में दिखाया गया है, सर्वेक्षण में शामिल सभी स्कूलों में से केवल 21% का पीटीआर 30 से कम था।

तालिका 2: छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर स्कूलों का प्रतिशत वितरण

छात्र-शिक्षक अनुपात	प्राथमिक विद्यालय (%)	उच्च-प्राथमिक विद्यालय (%)	सभी सैंपल स्कूल (%)
30 से कम	35	5	21
30 - 40	14	29	21
40 – 50	23	17	20
50 से अधिक	28	49	38

साक्षात्कार के दौरान, कई उत्तरदाता शिक्षकों ने बताया कि वे अपने स्कूलों को चलाने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की सख्त आवश्यकता के बारे में जानते हैं। लेकिन अभी और शिक्षक आने बाकी हैं। हमारे सैंपल स्कूलों में स्टाफ की कमी है। पीटीआर के लिए कुल छात्रों और आरटीई मानदंडों के आधार पर, सैंपल स्कूलों में 582 शिक्षकों (प्राथमिक में 71 और उच्च-प्राथमिक में 511) की कमी है। दूसरे शब्दों में, प्राथमिक विद्यालय आरटीई मानदंडों को पूरा करने के लिए आवश्यक शिक्षकों की संख्या के केवल 67% और उच्च-प्राथमिक 41% के साथ काम कर रहे हैं। यह कमी स्कूली शिक्षा प्रणाली में अन्य समस्याओं को बढ़ाती है।

इसके अलावा, हमारे सैंपल स्कूलों में शिक्षकों की अनुपासतिथि का उच्च स्तर दिखा। विद्यालय दौरे के दौरान औसतन केवल 58% नियुक्त शिक्षक ही विद्यालय परिसर में पाए गए। प्राथमिक विधालयों के लिए यह संख्या बढ़कर 63% हो गई और उच्च प्राथमिक विधालयों के लिए गिरकर 55% हो गई। शिक्षक अनुपासतिथि वाला संसाधन विहीन विद्यालय एक आपदा का नुस्खा है। यही 67% शिक्षकों के साथ काम करने वाले प्राथमिक विधालयों में केवल 63% शिक्षक ही ड्यूटी पर हैं; इसका मतलब है कि प्रभावी शिक्षक उपसतिथि मानक की केवल 42% है। उच्च प्राथमिक के लिए, यह स्तिथि और भी खराब होगी क्यूंकी वास्तविक रूप से निर्धारित संख्या में से केवल 23% शिक्षक ही ड्यूटी पर होंगे।

आशा की किरण यह है कि हमारे सैंपल में 40% से अधिक शिक्षक महिलाएँ हैं (परिशिष्ट 1: तालिका ए3)। महिला शिक्षकों की उपस्थिति लड़कियों की सुरक्षा एवं स्कूली शिक्षा पूरी करने की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। एक और सकारात्मक बात शिक्षण संवर्ग की सामाजिक संरचना है, जो ग्रामीण बिहार में जनसंख्या की सामाजिक संरचना के समान है। हमारे सर्वेक्षण में एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम पृष्ठभूमि के कई शिक्षक पाए गए (परिशिष्ट 1: तालिका ए 4)। ग्रामीण बिहार में शिक्षकों के बीच महिलाओं और सामाजिक रूप से वंचित समूहों का बढ़ता प्रतिनिधित्व स्कूलों को लोकतांत्रिक बनाने और शिक्षकों और बच्चों (या उनके परिवारों) के बीच सामाजिक दूरी को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

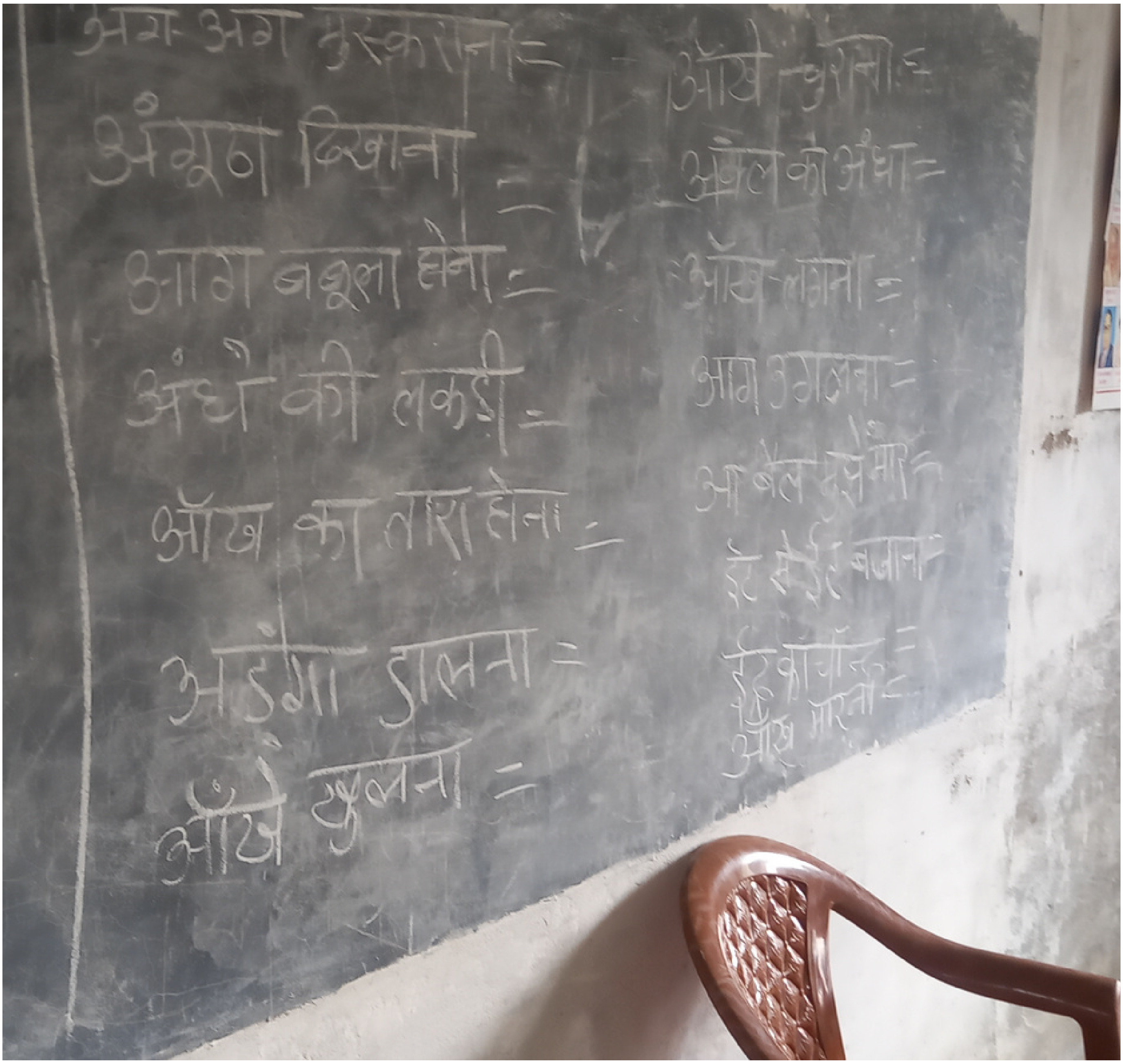

चित्र 1: अध्यापकों की कमी की वजह से अलग अलग कक्षा के बच्चे एक ही कक्ष में बैठ कर पढ़ते हैं
(श्रेय: प्रियांश सिन्हा और राहुल मालवीय)

बेहद कम उपस्थिति और नियमित ओवररिपोर्टिंग

विद्यार्थियों की अच्छी उपस्थिति एक सुचारु रूप से चलने वाले विद्यालय की पहचान है। इस पैमाने पर, उत्तर बिहार के अधिकांश स्कूल बहुत पिछड़े हुए हैं । जेजेएसएस सर्वेक्षण में उपस्थिति मापने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल किया गया। सर्वे टीमों को सबसे पहले उपस्थिति रजिस्टर की जांच कर आंकड़ा दर्ज करने को कहा गया। दूसरा, उनसे बच्चों की गिनती खुद करने को कहा गया. एक अच्छे स्कूल में, विद्यार्थियों की उपस्थिति औसत दिन में 90% से ऊपर और हर दिन 80% से ऊपर होने की उम्मीद करना अनुचित नहीं होगा। इस सर्वेक्षण में पाया गया कि प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति रजिस्टरों के अनुसार 44% से भी कम थी, और प्रत्यक्ष गणना के आधार पर इससे भी कम - केवल 23% थी। उच्च-प्राथमिक विद्यालयों के संबंधित आंकड़े समान थे: क्रमशः 40% और 20%। जैसा कि तालिका 3 में दिखाया गया है, केवल दो प्रतिशत स्कूलों (प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक दोनों में)[3] ने 60% या उससे अधिक की उपस्थिति दर्ज की। उपस्थिति के ये आंकड़े बेहद कम हैं और स्कूलों में अव्यवस्था का स्पष्ट संकेत हैं।

तालिका 3. सर्वेक्षण के दिन सैंपल स्कूलों में उपस्थिति दरें

	प्राथमिक विद्यालय	**उच्च-प्राथमिक विद्यालय**
नामांकित बच्चों की औसत संख्या (ए)	147	488
उपस्थित बच्चों की औसत संख्या: विद्यालय रजिस्टर (बी) के अनुसार सर्वेक्षण दल (सी) के अनुसार	 58 28	 178 92
हाजरी दर (%) स्कूल रजिस्टर के अनुसार (बी/ए) सर्वेक्षण दल के अनुसार (सी/ए)	 44 23	 40 20
60% से अधिक छात्र उपस्थिति वाले स्कूलों का अनुपात (%)	2	2
50% से अधिक छात्र उपस्थिति वाले स्कूलों का अनुपात (%)	23	7

[2] इन उपस्थिति आंकड़ों में सर्वेक्षण के समय शून्य उपस्थिति वाले 22 स्कूल शामिल हैं (उदाहरण के लिए ऐसे स्कूल जहां सर्वेक्षण टीम के पहुंचने पर बच्चे पहले ही जा चुके थे, या जहां बच्चे किसी स्थानीय शादी में आकर्षित हुए थे)। इन 22 स्कूलों को छोड़कर, प्राथमिक स्कूलों में उपस्थिति दर 23% से बढ़कर 30% और उच्च-प्राथमिक स्कूलों में 20% से बढ़कर 26% हो गई है।

हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि स्कूल में उपस्थिति की इतनी कम दर पहले कहीं देखी गई है। यह पता लगाने की तत्काल आवश्यकता है कि क्या यह ग्रामीण बिहार में एक सामान्य पैटर्न है, और यदि हां, तो उपस्थिति दर इतनी कम क्यों है। यह संभावना नहीं है कि यह केवल एक मौसमी प्रभाव था क्योंकि सर्वेक्षण अवधि गहन कृषि गतिविधि या प्रमुख त्यौहारों में से एक नहीं थी। पाँच आंशिक व्याख्याएँ दिमाग में आती हैं। सबसे पहले, नामांकन का कृत्रिम रूप से बढ़ा होना । दूसरा, कक्षा में गतिविधि की कमी और खराब शिक्षण संभवतः बच्चों को नियमित रूप से उपस्थित होने से हतोत्साहित करते हैं। तीसरा, हमने देखा कि कई बच्चे दोपहर के भोजन के बाद निजी ट्यूशन लेने के लिए स्कूल छोड़ देते हैं। चौथा, कोविड-19 संकट के दौरान स्कूलों के लंबे समय तक बंद रहने से बच्चों की स्कूल जाने की आदतें कम हो सकती हैं, या यहां तक कि यह धारणा भी बन सकती है कि स्कूल जाना महत्वपूर्ण नहीं है। पांचवां, यह संभव है कि "पाठ्यपुस्तकों के लिए डीबीटी" (नीचे चर्चा की गई) की अजीब प्रणाली ने इस पलायन को तेज कर दिया, न केवल कई बच्चों को पाठ्यपुस्तकों से वंचित किया बल्कि उन्हें निजी ट्यूशन के लिए नकद राशि भी प्रदान की। ये सभी संभावनाएँ चिंताजनक हैं।

कम उपस्थिति के अलावा, सर्वेक्षण में उपस्थिति रजिस्टर और वास्तविक उपस्थिति के बीच विसंगतियां पाई गईं: शिक्षक नियमित रूप से रजिस्टरों में उपस्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। ओवररिपोर्टिंग के लिए उनके पास दो सामान्य बहाने थे। पहला मध्याह्न भोजन से संबंधित था। बिहार में सरकार ने अंडे की कीमत पांच रुपये रखी है, जबकि बाजार में इसकी कीमत छ से सात रुपये हैं. इससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां स्कूलों में उपस्थित बच्चों के लिए पर्याप्त अंडे नहीं होंगे, जब तक कि शिक्षक मूल्य निर्धारण में अंतर को कवर करने के लिए उपस्थिति की अधिक रिपोर्ट न करे। यह बहाना थोड़ा बेकार है क्योंकि अंडे सप्ताह में केवल एक बार ही परोसे जाते हैं। दूसरा, शिक्षकों ने बताया कि यदि लगातार दिनों में उपस्थिति में बड़ा अंतर होता है, तो उन्हें अपने वरिष्ठों से कारण बताओ नोटिस प्राप्त होता है। ऐसे नोटिसों से बचने के लिए, शिक्षकों ने छात्रों की उपस्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर बताया।

चित्र 2: एक कक्षा जिसमे बमुश्किल ज़्यादा बच्चे उपस्थित नहीं हैं (श्रेय: प्रियांश सिन्हा और राहुल मालवीय)

लॉकडाउन के कारण सीखने में हानि हुई और उपचारात्मक उपाय सीमित हो गए

कोविड-19 संकट और उसके साथ लगे लॉकडाउन ने भारत में बच्चों की शिक्षा को बुरी तरह प्रभावित किया है। लगभग दो वर्षों के अंतराल के बाद, प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक विद्यालय अंततः फरवरी 2022 में फिर से खुल गए। लॉक्ड आउट: स्कूल शिक्षा पर आपातकालीन रिपोर्ट , बिहार सहित 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किए गए एक सर्वेक्षण के निष्कर्षों में पाया गया कि प्राथमिक या उच्च-प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित केवल 8% वंचित ग्रामीण बच्चे सर्वेक्षण के समय नियमित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे और 37% बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे थे। (बाखला, द्रेज़, खेरा और पैकरा, 2021) इसके अलावा, 48% बच्चे केवल कुछ शब्दों से अधिक पढ़ने में असमर्थ थे। अन्य अध्ययनों ने भी बच्चों की शिक्षा और भलाई पर लंबे समय तक स्कूल बंद रहने के प्रतिकूल प्रभाव का दस्तावेजीकरण किया है (यूनिसेफ इंडिया, 2021; घटक एट अल, 2020)।

बिहार में तो स्थिति और भी चिंताजनक है. जब उत्तरदाता शिक्षकों से पूछा गया कि क्या कक्षा 3-5 के छात्र स्कूल फिर से खुलने पर पढ़ना और लिखना भूल गए हैं, तो उत्तर स्पष्ट रूप से हाँ था। हमारे आधे सैंपल स्कूलों ने बताया कि उन कक्षाओं के "अधिकांश" छात्र पढ़ना और लिखना भूल गए थे। केवल 3% स्कूलों ने कहा कि उनमें से कोई भी पढ़ना-लिखना नहीं भूला है।

तालिका 4: कोविड के बाद बच्चों की पढ़ने और लिखने की क्षमताओं के बारे में शिक्षकों की धारणा

"जब 2022 की शुरुआत में स्कूल फिर से खुला, तो क्या आपने पाया कि कक्षा 3-5 के कुछ बच्चे पढ़ना-लिखना भूल गए थे?"			
	प्राथमिक विद्यालय (%)	**उच्च-प्राथमिक विद्यालय (%)**	**सभी सैंपल स्कूल (%)**
हाँ, उनमें से अधिकतर	58	47	52
हाँ कितने	5	17	11
हाँ कुछ	23	27	25
हाँ, बस कुछ ही	12	6	9
नहीं	**2**	**3**	**3**

नोट: यह "प्रतिवादी शिक्षकों" (प्रत्येक स्कूल में सबसे वरिष्ठ शिक्षक) का मूल्यांकन है। कॉलम टोटल = 100.

जेजेएसएस सर्वेक्षण से पता चलता है कि कोविड-19 झटकों की भरपाई के लिए बहुत कम काम किया गया है । जैसा कि तालिका 5 से पता चलता है, 85% उत्तरदाता शिक्षकों ने बताया कि उनके स्कूलों ने स्कूल के घंटे नहीं बढ़ाए। केवल पाँचवें प्राथमिक विद्यालयों और एक तिहाई उच्च-प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल समय के बाहर अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की गईं। संकट के समय की मांगों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों या स्वयंसेवकों की लामबंदी और शिक्षाशास्त्र में महत्वपूर्ण बदलाव जैसे उपाय रडार पर नहीं थे। कुछ अन्य उपाय जैसे कि विशेष शिक्षण सामग्री का वितरण, पाठ्यक्रम का सरलीकरण और गैर सरकारी संगठनों द्वारा सुविधा प्रदान किए गए ब्रिज पाठ्यक्रम किये गए, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वे कितने प्रभावी थे। उदाहरण के लिए, ब्रिज कोर्स को अक्सर अधूरा छोड़ दिया जाता था। इसके अलावा, उपयोगी उपायों के रूप में सामग्री वितरण का उल्लेख किए बिना, कई उत्तरदाता शिक्षकों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अतिरिक्त कक्षाओं, उपचारात्मक कक्षाओं और पुनरीक्षण से संबंधित उपायों से छात्रों को मदद मिली होगी।

तालिका 5: कोविड के बाद के उपचारात्मक उपाय

उत्तरदाता शिक्षकों का अनुपात (%) जिन्होंने कहा कि उनके स्कूल में उन बच्चों की मदद के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए थे जो पढ़ना और लिखना भूल गए थे:	**प्राथमिक विद्यालय**	**उच्च-प्राथमिक विद्यालय**
स्कूल के समय का विस्तार	15	15
स्कूल समय के अलावा अतिरिक्त कक्षाएं	21	33
विशेष शिक्षण सामग्री का वितरण	70	78
पाठ्यक्रम का सरलीकरण	60	54
ब्रिज कोर्स	55	54
छुट्टियाँ कम करना	25	20

पर्याप्त और प्रभावी उपचारात्मक उपायों के बिना, उत्तरी बिहार में प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक विद्यालय ऐसे चल रहे हैं जैसे कि कभी कोई स्कूल बंद नहीं हुआ और सीखने का नुकसान ही नहीं हुआ। यह बेहद परेशान करने वाली बात है, क्योंकि ये कक्षाएं सीखने की नींव बनाती हैं और ठोस नींव न होने से छात्रों के सीखने के समग्र पाठ्यक्रम और शैक्षिक अनुभव पर असर पड़ता है। उपचारात्मक उपायों की कमी से छात्रों के बीच मौजूदा शैक्षिक असमानताएँ भी बढ़ेंगी। जबकि शहरी स्कूलों के समर्थ छात्रों के पास अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा करने के तरीके हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले छात्रों के पास इस अवसर की कमी है और वे अपने नियंत्रण से परे स्थिति के लिए एक असमान कीमत चुकाते हैं।

चित्र 3: कुछ छात्र स्कूल के बाद के समय में खेल रहे हैं (श्रेय: शशांक सिन्हा और हर्ष राज)

बुनियादी ढांचे के बिना स्कूल

उत्तरी बिहार के स्कूलों में पाई जाने वाली सबसे गंभीर समस्याओं में से एक बुनियादी ढांचे, विशेषकर बुनियादी सुविधाओं की कमी है। अररिया के एक प्राथमिक विद्यालय के बारे में फील्डनोट्स स्थिति का स्पष्ट लेकिन सटीक वर्णन करते हैं: " कोई फर्नीचर नहीं, कम कक्षाएँ, कोई खेल का मैदान नहीं। एसएमसी फंड से बन रहे कुछ भवन अधूरे छोड़ दिए गए। कोई पुस्तकालय नहीं।" उच्च-प्राथमिक विद्यालयों का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर है लेकिन वे भी आदर्श स्थिति से बहुत दूर हैं। तालिका 6 सैंपल स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का सारांश प्रस्तुत करती है, जैसा कि सर्वेक्षण टीमों द्वारा देखा गया है। हम नीचे कुछ अधिक गंभीर दोषों पर संक्षेप में चर्चा करते हैं।

चारदीवारी: सैंपल स्कूलों में अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों (62%) और 19% उच्च-प्राथमिक विद्यालयों में कोई चारदीवारी नहीं थी। चारदीवारी के बिना, स्कूलों में बर्बरता, आवारा जानवरों, अनियंत्रित आगंतुकों और बच्चों के मुक्त निकास का खतरा रहता है।

खेल के मैदान: नहीं के बराबर प्राथमिक विद्यालय और हर पांचवे उच्च प्राथमिक विद्यालय में खेल के मैदान हैं जिन्हे "अच्छी" स्थिति में वर्णित किया जा सकता है। अधिकांश स्कूलों में, खेल के मैदान या तो अस्तित्व में नहीं हैं या चारदीवारी की कमी और अन्य रखरखाव के मुद्दों के कारण खराब स्थिति में हैं। जैसा कि सर्वेक्षण टीम के फ़ील्ड नोट्स में बताया गया है, खेल के मैदानों के बिना " स्वतंत्र रूप से खेलने में असमर्थता के कारण बच्चों का समग्र विकास बाधित हो जाता है।"

शौचालय: उत्तरी बिहार के स्कूल खुले में शौच से मुक्त नहीं हैं - इससे कोसों दूर हैं । प्राथमिक विद्यालयों के पांचवें और उच्च-प्राथमिक विद्यालयों के छठे हिस्से में शौचालय है ही नहीं । जिन स्कूलों में हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे शौचालय हैं जिन्हें "चलेगा" या "खराब" कहा जा सकता है, केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास "अच्छे" शौचालय हैं। कुछ स्कूलों में, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए केवल एक शौचालय था, जिसका उपयोग संभवतः कोई भी नहीं कर रहा था। शौचालयों की कमी भी शिक्षकों, विशेषकर महिला शिक्षकों के लिए भारी परेशानी का कारण बन सकती है।

जल आपूर्ति: केवल 8% प्राथमिक विद्यालयों में "अच्छी" जल आपूर्ति थी। उच्च-प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्थिति थोड़ी बेहतर थी, लेकिन वहां भी, आधे से भी कम में पानी की आपूर्ति थी जिसे सर्वेक्षण टीम ने "अच्छा" बताया था। अच्छी जल आपूर्ति के बिना, स्कूलों में अच्छी स्वच्छता बनाए रखना और बुनियादी रखरखाव करना कठिन है।

तालिका 6: बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का जांचकर्ताओं का आकलन

	प्राथमिक विद्यालय (%)			उच्च-प्राथमिक विद्यालय (%)		
	अच्छा	उदासीन [ए]	लापता [बी]	अच्छा	उदासीन [ए]	लापता [बी]
जलापूर्ति	8	80	12	42	56	2
प्रसाधन	16	61	23	40	45	15
घड़ी	12	25	63	49	32	19
बिजली फिटिंग	22	50	28	41	59	0
छत	55	35	10	66	32	2
दरवाजे	58	32	10	73	27	0
चारदीवारी	10	28	62	27	54	19
खाना पकाने का शेड	11	82	7	40	53	7
खेल का मैदान	2	70	28	22	61	17
पुस्तकालय	0	23	77	25	40	35

ए: "बहुत-बहुत" या "गरीब"।
बी: गैर कार्यात्मक, या बिल्कुल उपलब्ध नहीं।

बुनियादी सुविधाओं की कमी के अलावा, कक्षाओं, टेबल और कुर्सियों की भी अत्यधिक कमी है। अक्सर छात्र बाहर बरामदे या गलियारों में और टाट या चटाई पर बैठकर काम चलाते हैं । अररिया में सरकारी प्राथमिक विद्यालय ऋषिदेव टोला का निम्नलिखित केस अध्ययन, जिसमें 150 छात्र हैं और एक झोपड़ी में चलता है, बुनियादी ढांचे की अत्यधिक कमी की एक महत्वपूर्ण झलक प्रदान करता है जो उत्तरी बिहार में स्कूली शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है।

चित्र 4: अपर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले स्कूल में बरामदा में पढ़ाई होती है (श्रेय: हर्ष राज और शशांक सिन्हा)

प्राथमिक विद्यालय के रूप में एक पुआल-बांस की झोपड़ी

अररिया के सिकटी प्रखंड में ऋषिदेव टोला, प्लास्मानी ऋषिदेव जाति के लोगों की एक छोटी सी बस्ती है। यहां स्थित टोले और प्राथमिक विद्यालय का पता लगाना और उन तक पहुंचना बेहद कठिन था। यहां कोई मोटर योग्य सड़क नहीं है, केवल अनियमित रूप से बने रेतीले रास्ते हैं। दुख की बात है कि स्कूल इस वंचित परिदृश्य में फिट बैठता है। इसमें एक कक्षा है, जो पुआल और बांस से बनी एक अस्थायी झोपड़ी है। पतली छत वाली इस नाजुक संरचना में कई दरारें दिखाई देती हैं। न्यूनतम शिक्षण सुविधाओं (कोई ब्लैकबोर्ड, बेंच, टेबल नहीं) वाला यह आदिम स्कूल 'भवन' यहां नामांकित लगभग 150 छात्रों की प्राथमिक शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। हमारी यात्रा के दौरान, वहां कोई छात्र मौजूद नहीं था, हालांकि शिक्षक और कुछ स्थानीय लोगों ने जोर देकर कहा कि उपस्थिति आमतौर पर अधिक होती है। हालाँकि, यह विश्वास करना कठिन है कि यह कक्षा 150 बच्चों को समायोजित कर सकती है।

स्कूल के बुनियादी ढांचे में एक स्थायी खाना पकाने का शेड और दो शौचालय हैं, जो दोनों बंद थे। जबकि खाना पकाने का शेड अच्छी स्थिति में लग रहा था, शौचालय - जिसके बारे में हमें बताया गया था कि वह नए स्थापित किए गए थे - को रखरखाव की सख्त जरूरत थी। रसोइया ने हमें बताया कि दोपहर का भोजन प्रतिदिन बनाया जाता है, और छात्र आमतौर पर दोपहर के भोजन के बाद चले जाते हैं। परिसर में बिजली या पानी की कोई आपूर्ति नहीं है। विद्यालय परिसर में एक गाय चरती हुई दिखी। चारदीवारी के अभाव के कारण स्कूल के क्षेत्र को गांव के बाकी हिस्से से अलग करना मुश्किल था। हमारी यात्रा के दौरान इस रेतीले परिदृश्य में सूरज चमक रहा था, जिससे यह सवाल भी उठता है कि छात्र इतनी गर्मी में कैसे पढ़ाई कर सकते हैं।

कुल मिलाकर, बुनियादी ढांचे की दृष्टि से यह स्कूल हमारे द्वारा सर्वेक्षण किए गए सभी स्कूलों में सबसे खराब था। यह उत्तर बिहार में सार्वजनिक शिक्षा की दुखद चरम सीमा को उजागर करता है। एक ऐसा स्कूल जो अस्तित्व में है लेकिन उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक मामूली सुविधाएं भी नहीं हैं।

राहुल मालवीय, छात्र स्वयंसेवक, (एन एल एस आई यू बैंगलोर)

चित्र 5: ऋषिदेव टोला में प्राथमिक विद्यालय पुआल-बांस की झोपड़ी में चलता है (श्रेय: प्रियांश सिन्हा और राहुल मालवीय)

भवन विहीन विद्यालय

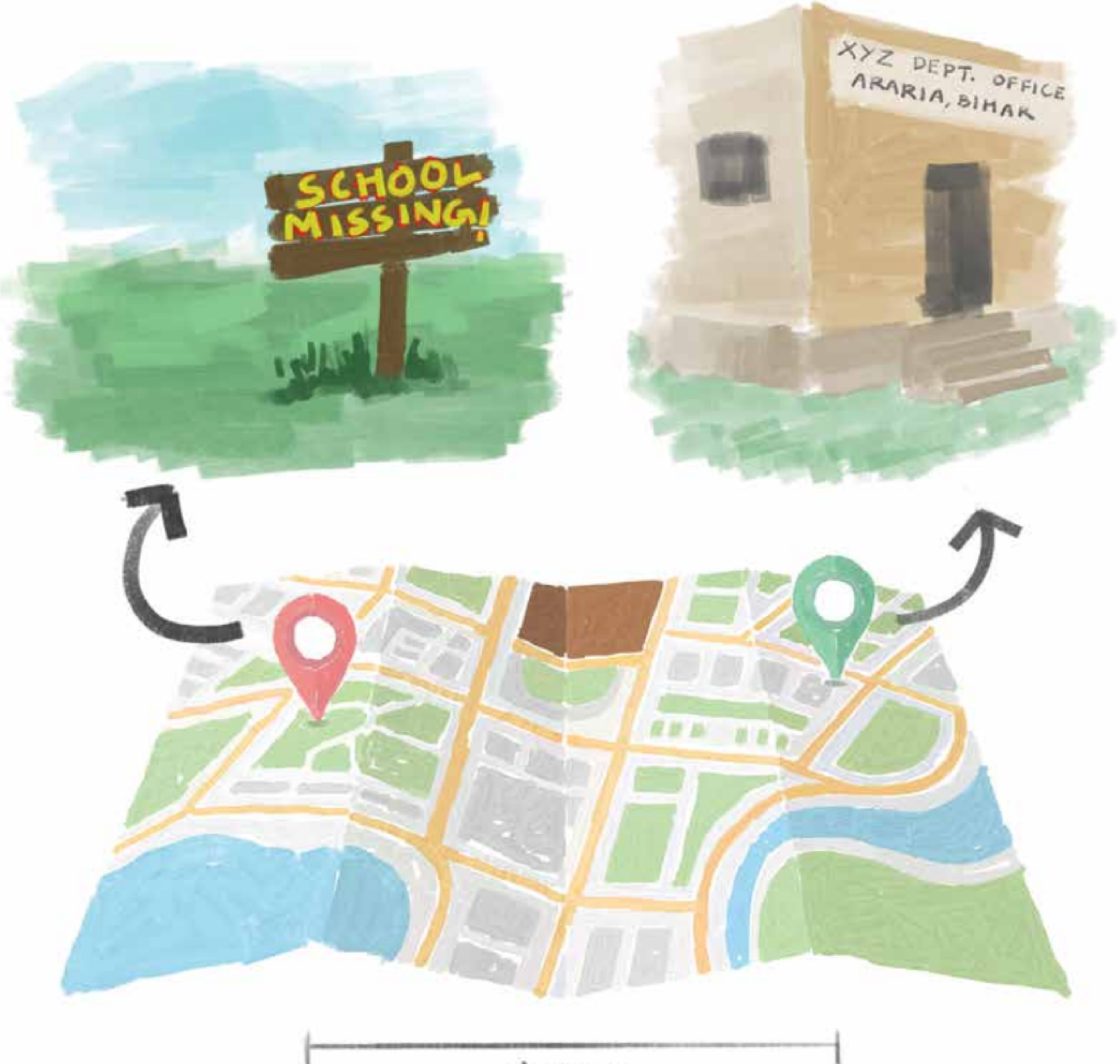

आरटीई अधिनियम के अनुसार, कुछ बुनियादी ढांचागत आवश्यकताएं हैं जिन्हें सभी सरकारी स्कूलों को पूरा करना होगा । उनमें से एक है पर्याप्त संख्या में कक्षाओं के साथ एक सभी मौसम के लिए उपयुक्त भवन, एक कार्यालय-सह-स्टोर-सह-प्रधान शिक्षक कक्ष, लड़कियों और लड़कों के लिए शौचालय, सभी बच्चों के लिए एक सुरक्षित और पर्याप्त पानी की सुविधा, एक खाना पकाने का शेड, एक खेल का मैदान और एक चारदीवारी। जेजेएसएस सर्वेक्षण से पता चलता है कि उत्तरी बिहार के सभी स्कूल ज्यादातर मामलों में लंबे अंतर से इन आवश्यकताओं से कम हैं।

सर्वेक्षण के सबसे चौंकाने वाले निष्कर्षों में से एक यह है कि 9% सैंपल स्कूलों (81 में से 7) के पास कोई इमारत नहीं है। ये स्कूल किसी अन्य सरकारी कार्यालय या भवन में चलते हैं, उस समुदाय से 5 किमी दूर तक जिसके लिए वे बने हैं। लंबी दूरी के कारण इन स्कूलों में नामांकन आमतौर पर काफी कम होता है। इनमें से कुछ स्कूलों के पास अपना कोई शिक्षक नहीं था - वे दूसरे स्कूल के शिक्षकों पर निर्भर थे जहाँ उन्हें एक कमरा आवंटित किया गया था।

लापता स्कूल भवनों पर हमारे सर्वेक्षण के निष्कर्ष आधिकारिक राज्य-स्तरीय आंकड़ों के अनुरूप हैं। एक हालिया आरटीआई (2023 की शुरुआत में दायर) के अनुसार, बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में से 7% के पास इमारतें नहीं हैं और वे समान परिस्थितियों में मौजूद हैं; इनमें से 120 स्कूल राज्य की राजधानी पटना के भीतर और उसके आसपास हैं। (Mishra, 2023)देश भर में स्कूल के बुनियादी ढांचे में बड़ी प्रगति के बावजूद, ये स्कूल और उनमें पढ़ने वाले छात्र अभी भी आरटीई अधिनियम से पहले के समय में अटके हुए हैं, जब स्कूल बिना भवनों के संचालित होते थे। यह बच्चों के शिक्षा के अधिकार का घोर उल्लंघन है और इस बात का निराशाजनक संकेत है कि बिहार की स्कूली शिक्षा प्रणाली बुनियादी मानदंडों को भी पूरा करने में असमर्थ है।

चित्र 6: बिहार में खुले में कक्षाएं नियमित हैं (श्रेय: प्रियांश सिन्हा और राहुल मालवीय))

भवन विहीन प्राथमिक विद्यालय

पीएस ऋषिदेव टोला, रामपुर अररिया जिले के अंदरूनी हिस्से में है और रामपुर- कोदरकट्टी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। हमें प्राथमिक विद्यालय ढूँढने में बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि स्कूल काअपना कोईभवन नहीं था। अपने भवन की जगह यह स्कूल, दूसरे प्राथमिक विद्यालय के भवन से संचालित होता है। दोनों सकूल, एक साथ चलते हैं, पीएस ऋषिदेव टोले को दो कक्षाएँ सौंपी गई हैं। जब हम वहां पहुंचे, तो हमें कार्यदिवस के दिन स्कूल का समय होने के बावजूद पीएस ऋषिदेव टोले में कोई छात्र नहीं मिला। पूछने पर शिक्षक ने बताया कि पीएस ऋषिदेव टोला की प्रधानाध्यापिका की मृत्यु के कारण विद्यालय के कामकाज में विलंब हुआ है.

ऋषिदेव टोले के पास निर्माण के लिए भूमि की कमी के कारण , प्राथमिक विद्यालय उस समुदाय से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर चल रहा था जिसके लिए इसे स्थापित किया गया था। 132 छात्रों के नामांकन के बावजूद, उनमें से केवल 30-40 ही नियमित रूप से कक्षाओं में आते हैं, जैसा कि ड्यूटी पर मौजूद शिक्षक ने बताया। स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि उपस्थिति वास्तव में बहुत कम थी। अभिभावक अपने छोटे बच्चों को स्कूल इस दर से नहीं भेजते कि बच्चों को जिस रास्ते से जाना है उस पर ट्रैफिक है और बिना निगरानी के बच्चों को उस पर से नहीं भेजा जा सकता। बुनियादी तौर पर स्कूल में दो कक्षाएँ हैं, कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों को एक कमरे में एक साथ पढ़ाया जाता है और कक्षा 4 और 5 के छात्रों को दूसरे कमरे में पढ़ाया जाता है।

दोनों कक्षाओं में बमुश्किल कोई बेंच थी, और छात्र पाठ के दौरान फर्श पर बैठे थे। पानी की कोई अलग व्यवस्था नहीं है और ऋषिदेव टोले के छात्र परिसर में एक हैंडपंप पर निर्भर हैं। वहाँ कोई अलग शौचालय, चारदीवारी या बिजली नहीं थी। ये सभी कमियाँ इस स्कूल को हमारे सर्वे में सबसे कम सुविधाओं वाले स्कूलों में से एक बनाती है|

हर्ष राज, छात्र स्वयंसेवक (एन एल एस आई यू बैंगलोर)

मध्याह्न भोजन में हैं संभावनायें, उसका फायदा स्कूल नहीं ले पा रहे

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सरकारी प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को गर्म पका हुआ मध्याह्न भोजन का अधिकार देता है। स्कूल में स्वादिष्ट, पौष्टिक, साझा भोजन बच्चों के बीच पोषण, उपस्थिति और एकजुटता में सुधार लाने में काफी मदद कर सकता है। इसके स्पष्ट लाभों के बावजूद, उत्तर बिहार में मध्याह्न भोजन (एमडीएम) कार्यक्रम को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले, संसाधनों की अपर्याप्तता मध्याह्न भोजन में भी आ जाती है। लगभग 20% सैंपल विद्यालयों (24% प्राथमिक और 17% उच्च-प्राथमिक) ने मध्याह्न भोजन चलाने के लिए अपर्याप्त धन होने की सूचना दी। भले ही 95% स्कूलों ने बताया कि वे प्रति बच्चा प्रति सप्ताह एक अंडा उपलब्ध करा रहे हैं, कई उत्तरदाता शिक्षकों ने शिकायत की कि एमडीएम बजट में अंडा भत्ता बाजार मूल्य से कम था। इसके अतिरिक्त, कई स्कूलों में स्वच्छ खाना पकाने को सुनिश्चित करने के लिए उचित खाना पकाने का शेड या साफ पानी की आपूर्ति नहीं है।

चित्र 7: स्कूल दौरे के दौरान मध्याह्न भोजन का आनंद लेते छात्र। (श्रेय: प्रियांश सिन्हा और राहुल मालवीय)

दूसरा, दो प्रणालियाँ हैं जिनके माध्यम से बिहार के स्कूलों में एमडीएम कार्यक्रम चलाया जाता है। खाना या तो स्कूल में पकाया जाता है या स्थानीय एनजीओ द्वारा लाया जाता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि एनजीओ पहले स्थान पर क्यों शामिल हैं, मध्याह्न भोजन पकाने के लिए एक समान प्रणाली की कमी भ्रम का कारण बनती है। बिहार से ऐसी कई खबरें आई हैं जहां मध्याह्न भोजन खाने के बाद बच्चे बीमार पड़ गए हैं (Jha, 2023)। पिछले महीने, बिहार के मानवाधिकार आयोग ने राज्य के शिक्षा विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किया था कि मध्याह्न भोजन ठीक से पकाया जाए (Hindu Bureau, 2023)। चूंकि कई स्कूलों को स्थानीय गैर-लाभकारी संस्थाओं के माध्यम से पका हुआ भोजन आपूर्ति की जाती है, इसलिए गुणवत्ता नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर, कई प्रतिवादी शिक्षकों ने शिकायत की कि एमडीएम कार्यक्रम एक अतिरिक्त बोझ था। उन्होंने शिकायत की कि इससे उन्हें पढ़ाने में समय लगता है और वे इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। दुर्भाग्य से, किसी भी उत्तरदाता ने एमडीएम जैसे कार्यक्रम के कई फायदों का उल्लेख नहीं किया।

अंत में, कुछ क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर शाकाहार को बढ़ावा देने के स्थानीय प्रयासों के कारण एमडीएम में अंडा खिलाने पर हमला हो रहा है। पवित्रता और प्रदूषण के ब्राह्मणवादी विचारों से प्रभावित होकर, ग्रामीण बिहार में कुछ समूह अपने अनुयायियों को मांसाहारी भोजन छोड़ने और शुद्धता प्राप्त करने के लिए उपवास रखने का निर्देश देते हैं। सर्वेक्षण टीम को कम से कम तीन स्कूलों में ऐसे नेताओं की आदमकद फ्रेम वाली तस्वीरें मिलीं जो इन मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। कभी-कभी ये तस्वीरें किचन शेड में भी मिलती थीं। सर्वेक्षण टीम के फ़ील्डनोट स्थिति को स्पष्ट करते हैं:

"सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि छात्रों को अंडे बिल्कुल नहीं दिए गए थे। प्रधानाध्यापक ने हमें सूचित किया कि स्थानीय लोगों के सामाजिक दबाव के कारण अंडा उपलब्ध नहीं कराया गया क्योंकि इसे गैर-शाकाहारी और अशुद्ध माना जाता है।"

चित्र 8: स्कूल परिसर में साधुओं की आदमकद तस्वीरें जो एमडीएम में अंडे को हतोत्साहित करने के लिए जाने जाते हैं (श्रेय: प्रियांश सिन्हा और राहुल मालवीय)

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी .बी.टी) के खतरे

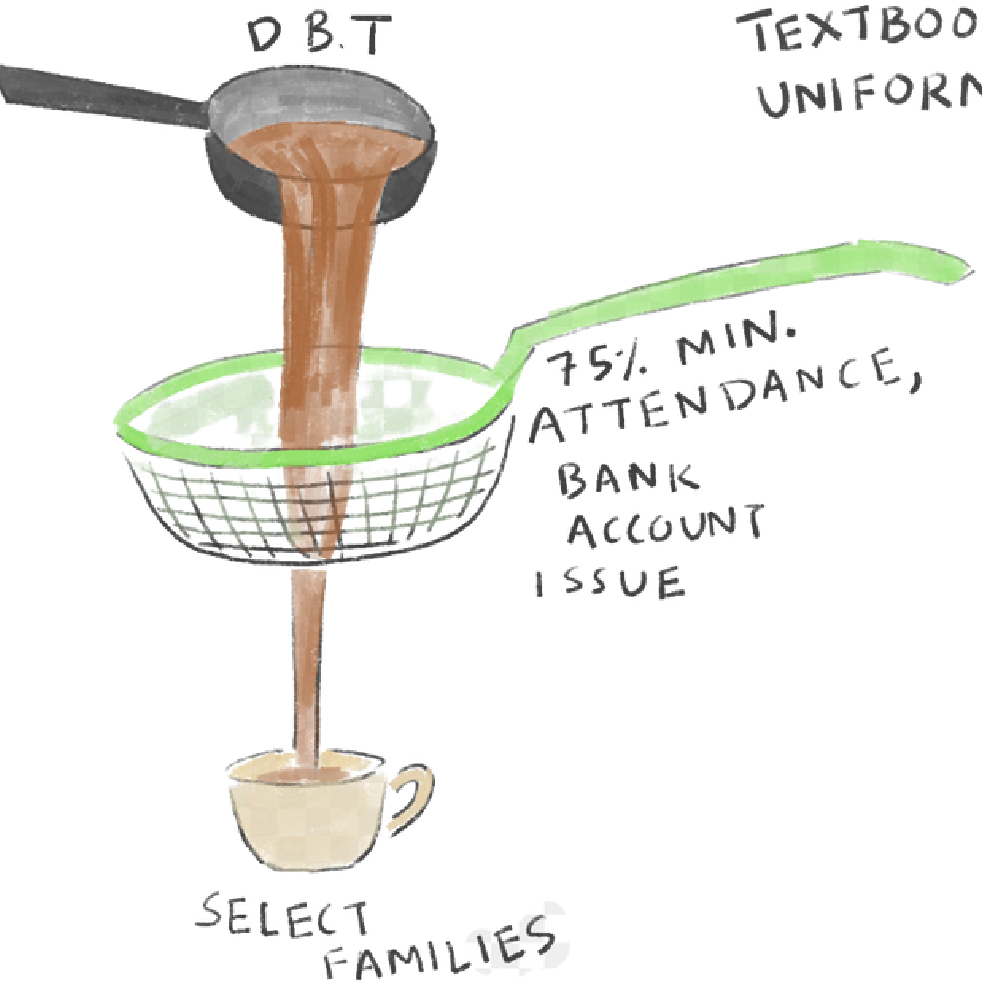

कुछ साल पहले तक, शिक्षा विभाग बिहार में स्कूली बच्चों को सीधे पाठ्यपुस्तकें और पोशाक प्रदान करता था (Kumar, 2022)। हालाँकि, इस केंद्रीकृत वितरण प्रणाली में आपूर्ति सम्बंधित गंभीर मुद्दे थे, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर लंबी देरी होती थी । उदाहरण के लिए, किताबें मध्य सत्र में स्कूलों तक पहुँचती थीं। 2017 में, कल्याण कार्यक्रमों में तथाकथित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के लिए केंद्र सरकार के दबाव के साथ, बिहार ने पाठ्यपुस्तकों और पोशाक के सीधे वितरण को नकद हस्तांतरण के साथ बदल दिया। डीबीटी प्रणाली के तहत, पैसा बच्चों के बैंक खातों (या जरूरत पड़ने पर उनके माता-पिता के खातों में) इस समझ से भेजा जाता है कि इसका उपयोग पोशाक और पाठ्यपुस्तकें खरीदने के लिए किया जाना है।

यह एक अजीब प्रणाली है, जो बिहार के लिए अद्वितीय है , कम से कम पाठ्यपुस्तकों के लिए (झारखंड ने हाल ही में वर्दी के लिए डीबीटी को अपनाया है)। इसके परिणाम का अनुमान लगाना कठिन नहीं है: अधिकांश स्कूलों में, कई बच्चों के पास पोशाक या पाठ्यपुस्तकें नहीं हैं। कुछ स्कूलों में अधिकांश बच्चों के पास पाठ्यपुस्तकें नहीं हैं। और निश्चित रूप से, जिनके पास पाठ्यपुस्तकें नहीं हैं वे अक्सर वंचित समुदायों से आते हैं। संक्षेप में, डीबीटी प्रणाली पूरी तरह से विफल है खासकर जहां तक पाठ्यपुस्तक का सवाल है ।

डीबीटी प्रणाली के तहत बच्चों को पाठ्यपुस्तकों से वंचित होने के दो अलग-अलग कारण हो सकते हैं। पहला, डीबीटी का पैसा किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं, और डीबीटी प्रणाली उन पर पाठ्यपुस्तकें खरीदने और बुनियादी आवश्यकताओं पर पैसा खर्च करने के बीच एक क्रूर विकल्प थोपती है। माता-पिता के साथ अनौपचारिक बातचीत से पता चलता है कि उनमें से कई लोग कुछ मामलों में निजी ट्यूशन सहित अन्य उद्देश्यों के लिए डीबीटी धन का उपयोग कर रहे हैं।
दूसरा, डीबीटी का पैसा हमेशा बच्चों या उनके माता-पिता तक नहीं पहुंचता है। पैसा 75% स्कूल उपस्थिति पर सशर्त है, और आधार से जुड़े बैंक खाते की भी आवश्यकता है। उपस्थिति की शर्त शायद सख्ती से लागू नहीं की गई है (और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उपस्थिति रजिस्टर बढ़ाए गए हैं), लेकिन यह अभी भी एक संभावित बाधा है। कुछ अभिभावकों को यह भी पता नहीं है कि पाठ्यपुस्तक का पैसा 75% उपस्थिति पर आधारित है। संयोग से, यह आरटीई अधिनियम का उल्लंघन है - स्कूली बच्चों को पाठ्यपुस्तकों पर बिना शर्त अधिकार है।

कभी-कभी आधार संबंधी समस्याओं के कारण भी डीबीटी भुगतान विफल हो जाता है। उदाहरण के लिए, आधार कार्ड और स्कूल रजिस्टर के बीच बच्चे के नाम में विसंगतियों या बैंक में अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) की समस्याओं के कारण ऐसा हो सकता है। डीबीटी प्रणाली में भुगतान अस्वीकृति की समस्याएं अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों (उदाहरण के लिए, मनरेगा और पेंशन) से परिचित हैं, और बिहार सरकार के स्वयं के आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि वे पाठ्यपुस्तक योजना को भी प्रभावित करते हैं: बिहार में स्कूल से संबंधित डीबीटी लेनदेन के लिए मेधासॉफ्ट पोर्टल के अनुसार , 11 सर्वेक्षण ब्लॉकों में 10,000 से अधिक छात्रों के बैंक खाते खारिज कर दिए गए हैं। अक्सर, माता-पिता को पता नहीं होता कि भुगतान क्यों अस्वीकार कर दिया गया है, या समस्या का समाधान कैसे किया जाए। इन मुद्दों से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है. और वैसे, स्कूली बच्चों से आधार मांगना आधार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है।

डीबीटी राशि के अभाव में, छात्र अभी भी पाठ्यपुस्तकें और पोशाक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। हमने पाया कि बिना पाठ्यपुस्तकों वाले कई बच्चे अपनी पढ़ाई में मदद के लिए निजी ट्यूशन पर निर्भर थे। कुछ ने किसी वरिष्ठ से उधार लिया था या अपने सहपाठियों के साथ साझा कर रहे थे। दूसरी ओर, पोशाक पाठ्यपुस्तक के मुकाबले अधिक दिखीं । कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने अपने बड़े भाई-बहनों के कपड़े हाथ से नीचे करके पहने हुए थे, जबकि कुछ ने दावा किया कि डीबीटी नहीं होने के बावजूद, उन्होंने अपने माता-पिता को पोशाक दिलाने के लिए मना लिया था। लेकिन कई लोग घर के कपड़ों में ही स्कूल आ रहे थे.

छात्रों को पोशाक और पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने में डीबीटी की विफलता के गंभीर परिणाम हैं। स्कूल जाते समय यूनिफॉर्म न होने से छात्रों पर मनोवैज्ञानिक-सामाजिक प्रभाव पड़ सकता है। पोशाक का मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच असमानता के दृश्य संकेतों को छिपाना है - यह उद्देश्य पूरी तरह से विफल हो जाता है जब कुछ छात्रों के पास पोशाक होती है और अन्य के पास नहीं। इसी तरह, पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षा प्रणाली में और वह भी ग्रामीण बिहार जैसे इलाके में जहां संसाधन की कमी है, पुस्तकों के बिना बच्चे बहुत कम सीखेंगे । जैसा कि सर्वेक्षण के दौरान कई शिक्षकों ने कहा था, पाठ्यपुस्तकों के बिना कोविड-19 लॉकडाउन उनके छात्रों के लिए और भी बुरा था क्योंकि भौतिक कक्षाओं और पाठ्यपुस्तकों के अभाव में उन्हें यह पता नहीं चल पाया था कि घर पर खुद से क्या पढ़ना है।

सैंपल स्कूलों के 20 शिक्षकों के साथ अनुवर्ती टेलीफोन पर बातचीत में, हमने पाया कि उनमें से लगभग सभी ने डीबीटी प्रणाली का विरोध किया और बेहतर समयबद्धता के साथ सीधे वितरण की वकालत की। शिक्षा विभाग अब पाठ्यपुस्तकों के सीधे वितरण की ओर लौट रहा है। हालाँकि, पोशाक के लिए डीबीटी जारी है।

चित्र 9: छात्र बिना पाठ्य पुस्तकों के क्लास संचालित करते हुए (श्रेय:शशांक सिन्हा और हर्ष राज)

मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक भाग के रूप में, केंद्र सरकार ने अपने 'एफएलएन कोर्सवर्क' के एक भाग के रूप में कक्षा 1 - 3 के लिए नई पुस्तकों का एक सेट शुरू किया है। इन पुस्तकों को केंद्र सरकार द्वारा मिशन 2027 के एक भाग के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जिस वर्ष तक इसका लक्ष्य कक्षा 3 या उससे नीचे के सभी बच्चों को बुनियादी अंकगणित, पढ़ना और लिखना सिखाना है। इसे प्राप्त करने के लिए, बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक स्कूल में एफएलएन पुस्तकें वितरित की गई हैं। सर्वेक्षण के अनुसार, हमने पाया कि 28% सैंपल स्कूलों (35% प्राथमिक और 22% उच्च-प्राथमिक) को वर्ष के लिए एफएलएन किताबें उपलब्ध नहीं कराई गई थीं। जिन स्कूलों में एफएलएन वितरित किया गया था, उनमें से 70% ने पाया कि किताबें काफी उपयोगी थीं। ऐसे स्कूल भी थे जहां सर्वेक्षण टीम ने पाया कि एफएलएन किताबें अभी भी उनके कार्डबोर्ड बक्से में सीलबंद पैक हैं।

यह पाया गया है कि चूंकि एफएलएन पाठ्यपुस्तकें डीबीटी के माध्यम से नहीं बल्कि स्थानीय ब्लॉक संसाधन केंद्र के माध्यम से स्कूल तक पहुंचती हैं, ऐसे मामलों में जहां स्कूलों में मानक पाठ्यपुस्तकें नहीं थीं, एफएलएन किताबें ही छात्रों के लिए उपलब्ध हो गईं। यह देखना बाकी है कि क्या वे निष्क्रिय व्यवस्था में कोई वास्तविक बदलाव ला सकते हैं।

चित्र 10: अस्थायी पुस्तकालय (श्रेय: हर्ष राज और शशांक सिन्हा)

निजी ट्यूशन जवाब नहीं हो सकता

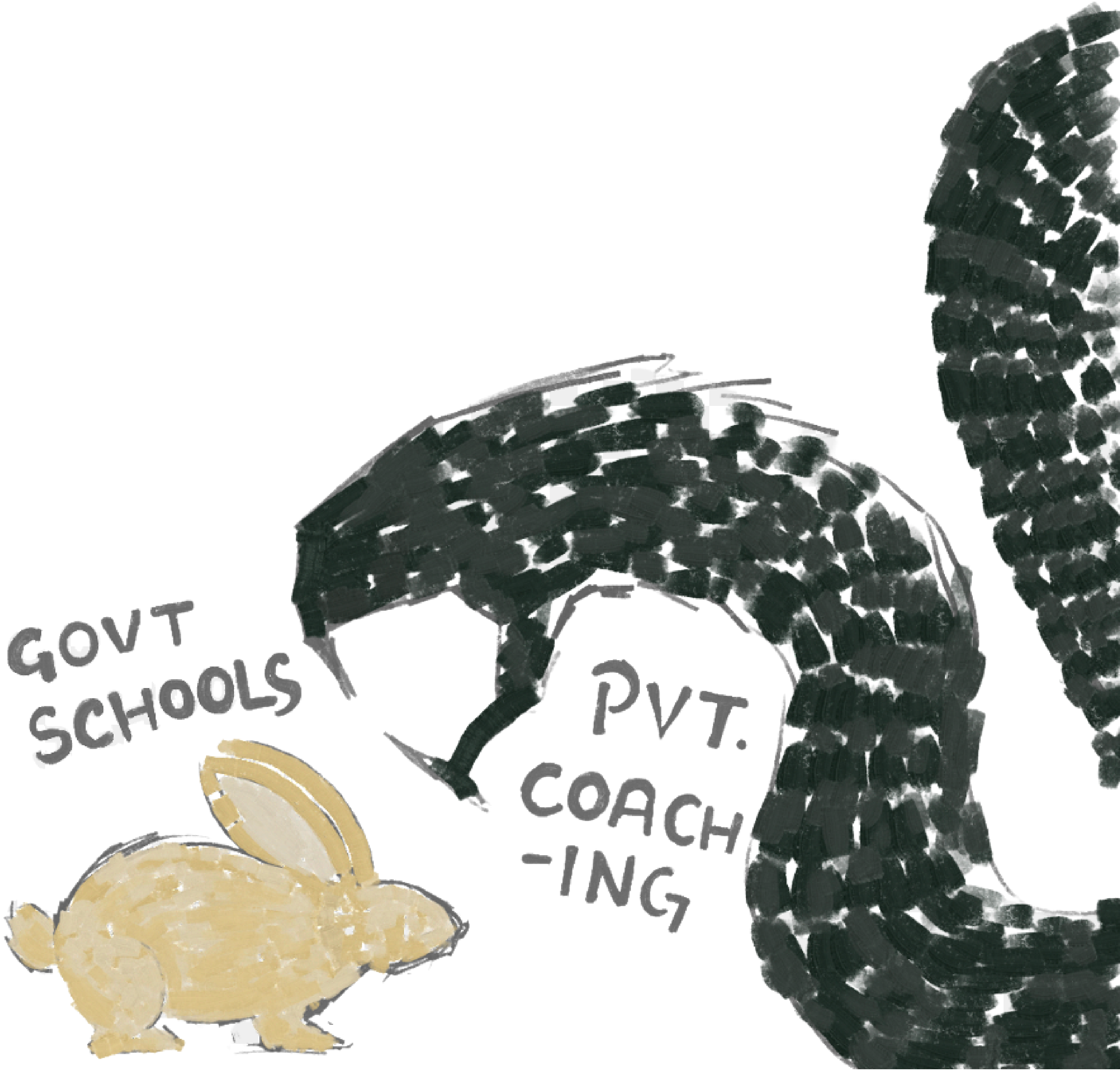

सरकारी स्कूलों की इस ख़राब स्थिति को देखते हुए, जैसा कि पहले भी उजागर किया जा चुका है, कई छात्र निजी ट्यूशन पर निर्भर हैं। कई स्कूलों में, सर्वेक्षण टीम ने पाया कि छात्र दोपहर के भोजन के बाद निजी ट्यूशन के लिए निकल गए थे। अन्य में, छात्र स्कूल देर से आए क्योंकि स्कूल का समय कोचिंग सेंटर के समय से मेल नहीं खाता था। जबकि निजी ट्यूशन विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों में होते हैं, उनमें से अधिकांश गांवों या बाज़ारों में साधारण प्रतिष्ठान होते हैं । हालांकि बुनियादी ढांचे में छोटे और संयमित, निजी ट्यूशन बहुत लोकप्रिय हैं और ग्रामीण उत्तर बिहार में असफल स्कूली शिक्षा प्रणाली के प्रतिस्थापन के रूप में काम करना शुरू कर दिया है। निजी ट्यूशन पर निर्भरता इतनी बढ़ गई है कि यह व्यावहारिक रूप से सरकारी स्कूलों में सभी शिक्षण सीखने की जगह ले रही है। ख़राब सरकारी स्कूलों और निजी ट्यूशन के बीच एक गठजोड़ बन गया है, जहाँ स्कूल की भूमिका केवल दोपहर का भोजन उपलब्ध कराने और परीक्षाओं की व्यवस्था करने तक ही सीमित रह गई है।

हालाँकि, निजी ट्यूशन में कई समस्याएं हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, वे शिक्षा का बाजारीकरण कर, पैसा देने की क्षमता के आधार पर शिक्षा प्रदान कर पूर्व असमानताओं को सुदृढ़ करते हैं। इस क्षेत्र में गरीबी और लिंग निजी शिक्षा की पहुंच निर्धारित करते हैं। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों और लड़कियों की तुलना में समर्थ समूहों के बच्चों और लड़कों की निजी ट्यूशन में भाग लेने की अधिक संभावना है। दूसरा, निजी ट्यूशन विनियमन और जवाबदेही से रहित हैं। वे स्थान, स्वच्छता, स्वच्छता, लोकतांत्रिक कार्य संस्कृति या अच्छे सीखने के माहौल के अन्य आवश्यक तत्वों से संबंधित किसी भी मानदंड को पूरा किए बिना अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं। अंत में, निजी ट्यूशन बच्चों के समग्र विकास के लिए बहुत कम चिंता के साथ परीक्षाओं और अंकों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए, निजी ट्यूशन सक्रिय स्कूलों का प्रतिस्थापन नहीं बन सकते और न ही बनने चाहिए।

चित्र 11: अनाकर्षक स्कूल कम उपस्थिति में तब्दील हो जाते हैं
(श्रेय: प्रियांश सिन्हा और राहुल मालवीय)

शिक्षा का अधिकार कानून का बड़े पैमाने पर उल्लंघन

जैसा कि अब तक स्पष्ट हो जाना चाहिए, चयनित स्कूलों में यदि सभी नहीं तो अधिकांश सरकारी स्कूल आरटीई अधिनियम का उल्लंघन करते हैं। उनमें से केवल 21% का छात्र-शिक्षक अनुपात निर्धारित अधिकतम 30 से कम था। बुनियादी ढाँचा बड़े पैमाने पर अनुपस्थित है, किसी भी प्राथमिक विद्यालय मैं पानी, बिजली और चालू अवस्था में शौचालय नहीं हैं, और केवल 22% उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पानी, बिजली और चालू अवस्था में शौचालय हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कक्षा, एक चारदीवारी, एक खेल का मैदान और एक ठीक ठाक रसोई शेड - सभी अनिवार्य सुविधाएं --बड़ी संख्या में सैंपल विद्यालय गायब थे या जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे । चौंकाने वाली बात यह है कि 9% के पास अपनी कोई इमारत नहीं थी। अंत में, पाठ्यपुस्तकों और यूनिफॉर्म पर 75% उपस्थिति की शर्त है , और कई बच्चों के पास यह शर्त पूरी करने के बावजूद भी नहीं है - यह फिर से आरटीई अधिनियम का उल्लंघन है।

ये स्कूल आरटीई कानून के नियमों का उल्लंघन कर बिहार के बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं. सार्वजनिक स्कूलों को ऐसी गंभीर परिस्थितियों में चलने की अनुमति देकर, राज्य सरकार अपनी आबादी को गरीबी और असुरक्षा से बाहर निकलने की संभावनाओं को छीन रही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस सर्वेक्षण में अध्ययन किए गए स्कूलों की स्थिति विलुप्त होने के कगार पर है। इसका सबसे बड़ा सूचक बेहद कम उपस्थिति के आंकड़े हैं. जैसा कि कई शिक्षकों ने दावा किया है, यह स्पष्ट हो रहा है कि बच्चे और माता-पिता सरकारी स्कूलों को दोपहर के भोजन और वार्षिक परीक्षाओं की जगह के रूप में देख रहे हैं। औपचारिक शिक्षा के लिए वे निजी ट्यूशन पर निर्भर हैं। लेकिन यह देखते हुए कि निजी ट्यूशन, कोचिंग सेंटर और शिक्षा का व्यावसायीकरण पहुंच, जवाबदेही, समानता और गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों से भरा है, यह बच्चे, विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे भारी कीमत चुका रहे हैं।

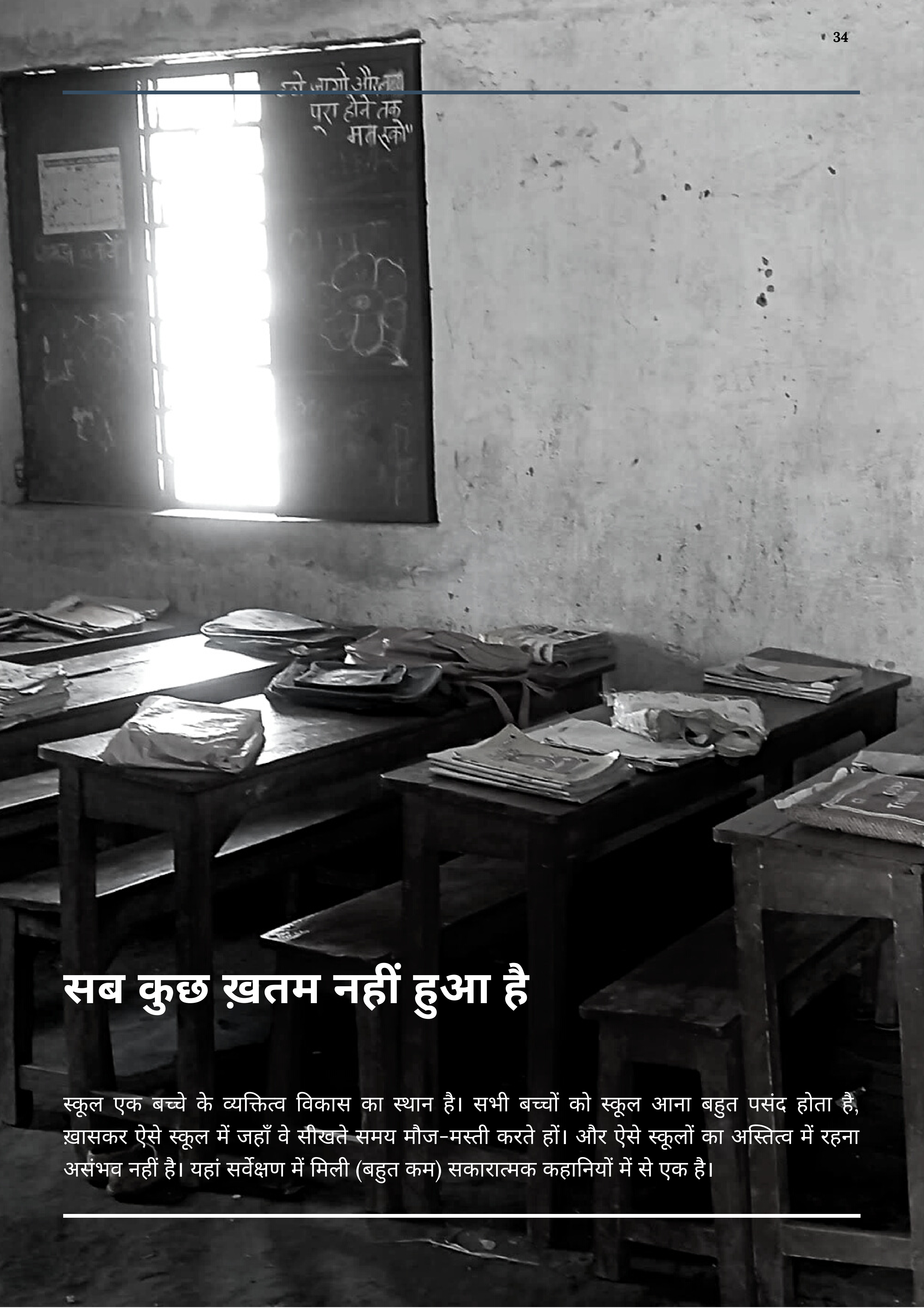

सब कुछ ख़तम नहीं हुआ है

स्कूल एक बच्चे के व्यक्तित्व विकास का स्थान है। सभी बच्चों को स्कूल आना बहुत पसंद होता है, ख़ासकर ऐसे स्कूल में जहाँ वे सीखते समय मौज-मस्ती करते हों। और ऐसे स्कूलों का अस्तित्व में रहना असंभव नहीं है। यहां सर्वेक्षण में मिली (बहुत कम) सकारात्मक कहानियों में से एक है।

माध्यमिक विद्यालय चरघरिया आशा की किरण

सिकटी , अररिया में यूएमएस चारघरिया उन सबसे अच्छे स्कूलों में से एक था, जहां हमने सर्वेक्षण के दौरान दौरा किया। स्कूल का बुनियादी ढांचा उत्कृष्ट था, और स्कूल का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह से किया गया था। दीवारों को हाल ही में रंगा गया था और छात्रों के लिए पर्याप्त कक्षाएँ थीं। उपस्थित सभी छात्र अन्य स्कूलों के विपरीत, जहां छोटे छात्रों को फर्श पर चटाई पर बैठाया गया था, मेज और कुर्सियों पर बैठे थे। प्रत्येक कक्षा में चालू रोशनी और पंखे थे। पूरे विद्यालय को चारों ओर से घेरने वाली चहारदीवारी पर्याप्त ऊंचाई की थी। हैंडपंपों एवं नलों के माध्यम से पानी की समुचित उपलब्धता थी। खाना पकाने का शेड भी साफ़ और सुव्यवस्थित था। शौचालय खुले थे और उपयोग के लिए अच्छे थे। इसके अलावा, चारदीवारी होने के कारण छात्र शौचालय का उपयोग कर रहे थे। एकमात्र चीज़ जो गायब थी वह थी एक पुस्तकालय कक्ष। पुस्तकालय की पुस्तकें कार्यालय में रखी जाती थीं और छात्र अपने शिक्षकों से उन्हें मांग सकते थे।

स्कूल में एक अच्छा छात्र -शिक्षक अनुपात था जो लगभग आरटीई मानदंडों को पूरा करता है। अधिकांश छात्र स्कूल की पोशाक पहने हुए थे और अपनी किताबें और कॉपियाँ स्वयं लाए थे। हर कक्षा में शिक्षक मौजूद थे और अध्ययन-अध्यापन चल रहा था। जब हम स्कूल का सर्वेक्षण कर रहे थे, तो हमने छात्रों को मध्याह्न भोजन परोसते हुए भी देखा। भोजन निर्धारित मेनू के अनुसार तैयार किया गया था और विद्यालय में ही पकाया जा रहा था। सरकार के निर्देशानुसार विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को प्रत्येक सप्ताह एक अंडा भी उपलब्ध कराया गया।

यूएमएस चारघरिया को भी अन्य सरकारी स्कूलों की तरह समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह इन समस्याओं के बावजूद समाधान निकालने और अपने सभी छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। शिक्षकों ने हमें बताया कि उपस्थिति में कठिनाई होती है क्योंकि बच्चों को अक्सर खेतों में काम करने के लिए भेजा जाता है। इससे निपटने के लिए शिक्षक एसएमसी बैठकों में अभिभावकों को अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे माता-पिता को अपने बच्चों के लिए पोशाक और किताबें खरीदने के लिए मनाते हैं एवं अन्य उद्देश्यों के लिए डीबीटी पैसे का उपयोग न करने के लिए प्रेरित करते हैं। अतीत में कार्यालय से इनवर्टर और वायरिंग जैसी चीजें चोरी होने की घटनाएं हुई थीं, लेकिन फिर भी, धन के कुशल प्रबंधन के कारण, स्कूल का रखरखाव अच्छी तरह से किया गया था। यूएमएस चरघरिया 'अच्छी' स्कूली शिक्षा के सबसे करीबियों में से एक है और यह दर्शाता है कि बिहार में प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, ऐसे स्कूल मौजूद हैं जो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।

प्रियांश सिन्हा, छात्र स्वयंसेवक (एन एल एस आई यू बैंगलोर)

यूएमएस चारघरिया की तरह , कुछ अन्य स्कूल सभी चुनौतियों के बावजूद अच्छी तरह से प्रबंधित थे। उन सभी में एक बात समान थी और वह थी समर्पित शिक्षकों का होना । टूटी हुई व्यवस्था में भी, एक कड़ी मेहनत करने वाला शिक्षक बदलाव ला सकता है। जोशीले और जिम्मेदार शिक्षकों के बिना, बुनियादी ढांचे की दृष्टि से परिपूर्ण स्कूल में भी सार्थक शिक्षा नहीं मिल सकती है। इसलिए, शिक्षकों की भूमिका एक प्रमुख कारक के रूप में उभरी जिसने इन स्कूलों को अच्छी तरह से संचालित किया। इसके अतिरिक्त, इन स्कूलों में तुलनात्मक रूप से बेहतर बुनियादी ढांचा था, जिसमें बिजली की आपूर्ति, अच्छी तरह से बनाए रखा पुस्तकालय और फर्श पर टाइलें थीं। ये ऐसे स्कूल थे जहां छात्रों की उपस्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर थी। अच्छी उपस्थिति सुनिश्चित करना अक्सर स्कूल के प्रति बच्चों और उनके माता-पिता की भावनाओं और अपेक्षाओं का परिणाम होता है। एक अच्छी तरह से बनाए गए स्कूल को नामांकित छात्रों और उनके माता-पिता द्वारा गंभीरता से लिया जाना निश्चित है। ये सकारात्मक उदाहरण इस बात को रेखांकित करते हैं कि उत्तर बिहार के सरकारी स्कूलों में स्वाभाविक रूप से कुछ भी दोषपूर्ण नहीं है। प्रत्येक बच्चे की शिक्षा और भलाई के लिए शिक्षकों, सरकार और समाज का जुनून और जिम्मेदारी स्कूलों की खराब स्थिति को बदलने में बहुत बड़ा अंतर ला सकती है।

चित्र 12: स्कूल की लाइब्रेरी दिखाते शिक्षक (श्रेय: हर्ष राज और शशांक सिन्हा)

झारखंड की तुलना में बिहार के स्कूलों का प्रदर्शन कैसा है?

ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड (जीवीएसजे) द्वारा किए गए इसी तरह के सर्वेक्षण पर आधारित एक रिपोर्ट, क्लासरूम में निराशा, झारखंड में प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक स्कूलों की निराशाजनक स्थिति को सामने लाती है। (ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड, 2022) जैसा कि नीचे दी गई तुलनात्मक तालिका में देखा जा सकता है, बिहार और झारखंड में स्कूल आदर्श से बहुत दूर हैं। हालाँकि दोनों राज्यों में क्या गायब है और क्या मौजूद है, इसमें मतभेद हैं।

	बिहार	झारखण्ड
छात्र शिक्षक अनुपात	21% विद्यालय RTE को मानते हैं	36% विद्यालय RTE को मानते हैं
छात्र उपसतिथि	23% प्राथमिक विद्यालय में और 20% उच्च प्राथमिक विद्यालय	68% प्राथमिक विद्यालय में और 58% उच्च प्राथमिक विद्यालय
लॉकडाउन का पढ़ाई पर असर और उपाय	बच्चे पढ़ना लिखना भूल गए, उपाय ज़्यादा नहीं मिले, निजी ट्यूशन से मदद हुई	बच्चे पढ़ना लिखना भूल गए, उपाय पूरे नहीं किए गए
बुनियादी ढांचा	बेहद कम टेबल चैर, बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, स्थानीय जनता तोड़ फोड़ करती है	बुनियादी ढांचा कमज़ोर है लेकिन स्थानीय लोग देख भाल करते हैं
महिला शिक्षक	40% प्रतिशत से ऊपर	21% प्राथमिक विद्यालयों में और 35% उच्च प्राथमिक विद्यालयों में
एफ. एल. एन	30% स्कूलों में किताबें नहीं थी, DBT के ना होने पर मदद करता है	किताबें मिली लेकिन अध्यापकों को इस्तिमाल करना नहीं सिखाया
मध्यान भोजन	अंडा बाज़ार और सरकार अलग दाम पर रखती है, हर बच्चे को प्रति सप्ताह एक अंडा काम है, स्थानीय साधु बच्चों को अंडा खाने को मना करते हैं, निजी संस्थायो को मध्याम भोजन से हटाना चाहिए	अंडों को हफ्ते में दो बार से 6 बार करना चाहिए, अंडा और मध्यान भोजन की राशि पर्याप्त समय पर स्कूल भेजनी चाहिए
किताबें और स्कूल ड्रेस	गंभीर स्तिथि है और किताबें काफी कम हैं	किताबें और ड्रेस हैं लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए बच्चों की संख्या के हिसाब से
भवन विहीन स्कूल	9% विद्यालयों में भवन नहीं है	भवनविहीन तो नहीं लेकिन मर्जर स्कूल हैं
निजी ट्यूशन	स्कूल से ज़्यादा माता-पिता निजी ट्यूशन पर भरोसा करते हैं	स्कूल से ज़्यादा माता-पिता निजी ट्यूशन पर भरोसा करते हैं
शौचालय और खुले में शौच	शौचालय या तो इस्तिमाल के लायक नहीं हैं, या फिर बंद रहते हैं, बच्चे अक्सर स्कूल के परिसर के पीछे शौच करते हैं	शौचालयों में पानी की कमी है लेकिन फिरभी बच्चे इस्तिमाल करते हैं अगर पानी हो तो
एकल शिक्षक विद्यालय	10% प्राथमिक विद्यालय	30% प्राथमिक विद्यालय

चित्र 9: बिहार और झारखंड के स्कूलों के बीच तुलना

कई मामलों में बिहार का प्रदर्शन झारखंड से भी खराब है: छात्र-शिक्षक अनुपात बदतर; विद्यालय में उपस्थिति दर कम होना; निराशाजनक बुनियादी ढाँचा; दोपहर के भोजन में कम अंडे; गायब पाठ्यपुस्तकें और वर्दी; अस्वच्छ एवं खराब रखरखाव वाले शौचालय; और भवनहीन विद्यालय! दूसरी ओर, झारखंड में सरकारी स्कूल एकल-शिक्षक स्कूलों (लगभग 30%) का केंद्र होने के मामले में बदतर स्थिति में हैं; कार्यबल में कम महिला शिक्षक; और बिना प्रशिक्षण के एफएलएन का वितरण किया जा रहा है। निस्संदेह, अधिकांश मामलों में, दोनों राज्यों में स्थिति गंभीर है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि झारखंड में प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक विद्यालय बिहार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

चित्र 13: कक्षाओं के भीतर टेबल और कुर्सियों की कमी के कारण छात्रों को अपने स्कूल के बरामदे में बैठना पड़ता है (श्रेय: प्रियांश सिन्हा और राहुल मालवीय)

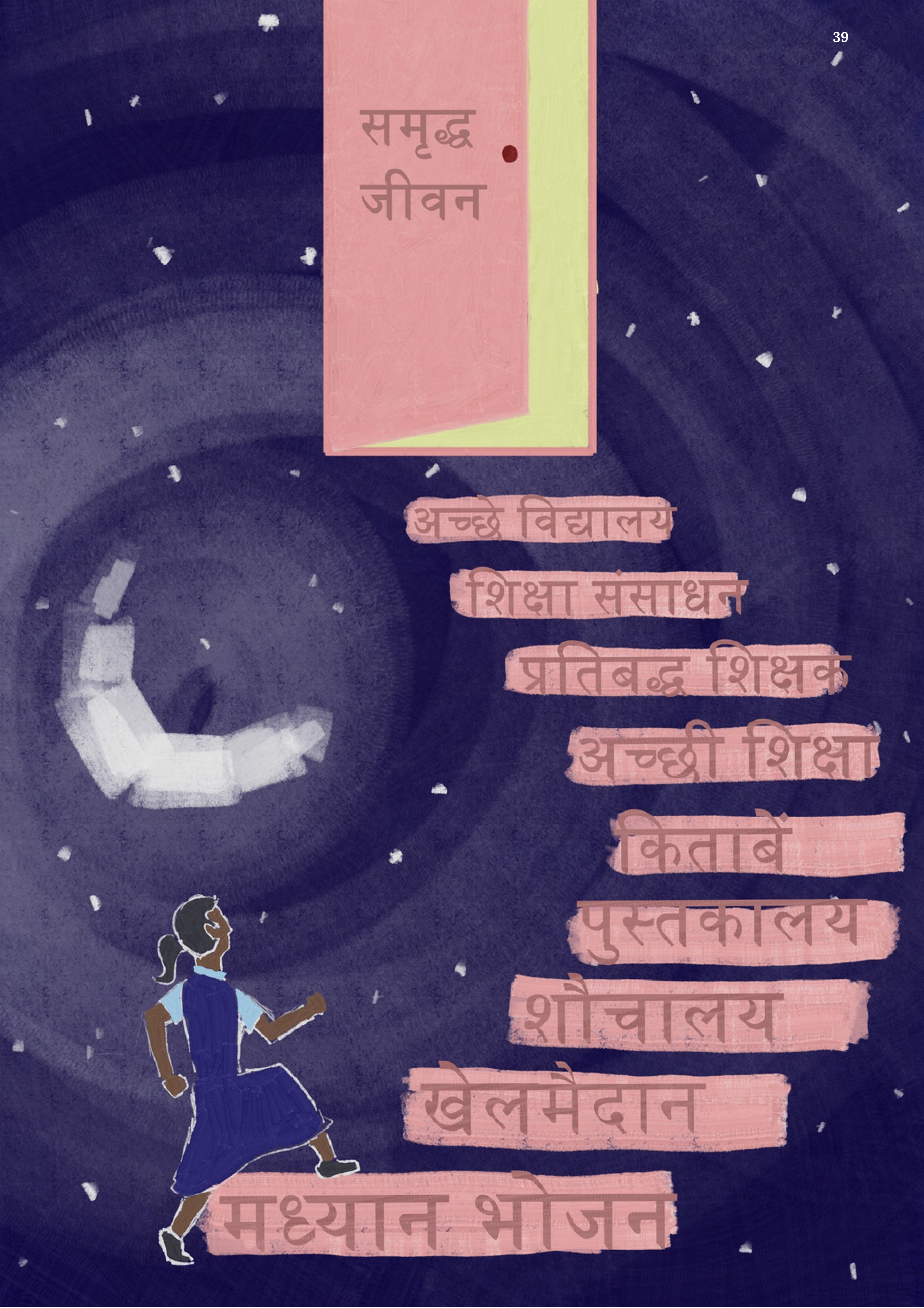
समृद्ध
जीवन
अच्छे विद्यालय
शिक्षा संसाधन
प्रतिबद्ध शिक्षक
अच्छी शिक्षा
किताबें
पुस्तकालय
शौचालय
खेलमैदान
मध्यान भोजन

उत्तर बिहार में स्कूली शिक्षा व्यवस्था की खस्ता हालत को बदलने का समय आ गया है

भले ही मुट्ठी भर स्कूल जो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उम्मीद जगाते हैं, पर यह सर्वेक्षण उत्तर बिहार में स्कूली शिक्षा प्रणाली की एक चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। जैसा कि नीचे दिए गए रिपोर्ट कार्ड से पता चलता है, यदि सभी नहीं तो अधिकांश पहलुओं में, इस क्षेत्र के प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक विद्यालय न्यूनतम मानकों को पूरा करने में विफल रहते हैं।

रिपोर्ट कार्ड: प्राथमिक विद्यालय

प्राथमिक विद्यालय का अनुपात (%)			
छात्र उपसतिथि 50% से ऊपर	23%	कम से कम पाँच क्लासरूम वाले	35%
30 से कम पीटीआर वाले	35%	शौचालयों की अच्छी स्तिथि वाले	16%
मिडडे मील के लिए पर्याप्त राशि वाले	75%	खेल मैदान वाले	72%
कम से कम पाँच टीचर वाले	12.5%	बिजली, पानी और शौचालय (सभी तीन) वाले	0%
कम से कम एक महिला टीचर वाले	78%	लाइब्रेरी की किताबों वाले	23%

हाँ नहीं

जैसा कि ऊपर दिए गए रिपोर्ट कार्ड में देखा जा सकता है, उत्तर बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बहुत कम है। शिक्षकों की भारी कमी है, केवल 35% स्कूल ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निर्धारित पीटीआर मानदंडों को बनाए रखते हैं।

केवल 12.5% प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम पाँच शिक्षक हैं - प्रत्येक कक्षा के लिए एक। बुनियादी ढांचे के मामले में भी इन स्कूलों का स्कोर काफी खराब है। सैंपल के एक भी प्राथमिक विद्यालय में सुचारू स्थिति में बिजली, पानी की आपूर्ति और शौचालय नहीं थे! केवल 35% के पास पाँच कक्षाएँ थीं, बाकी को बहु-कक्षा शिक्षण का अभ्यास करना पड़ता था जो सीखने के परिणामों को कम करने के लिए जाना जाता है। 23% प्राथमिक विद्यालयों के पास लाइब्रेरी थी और 72% के पास खेल मैदान था। तीन-चौथाई ने मध्याह्न भोजन के लिए पर्याप्त धनराशि होने का दावा किया।

रिपोर्ट कार्ड: उच्च-प्राथमिक विद्यालय

उच्च प्राथमिक विद्यालय का अनुपात (%)			
छात्र उपसतिथि 50% से ऊपर	7%	कम से कम आठ क्लासरूम वाले	63%
30 से कम पीटीआर वाले	5%	शौचालयों की अच्छी स्तिथि वाले	40%
मिडडे मील के लिए पर्याप्त कोष वाले	81%	खेल मैदान वाले	83%
कम से कम आठ टीचर वाले	63%	बिजली, पानी और शौचालय (सभी तीन) वाले	22%
कम से कम चार महिला टीचर वाले	65%	लाइब्रेरी की किताबों वाले	65%

हाँ नहीं

उच्च-प्राथमिक विद्यालय कुछ हद तक बेहतर स्थिति में हैं। उनके विद्यार्थियों की उपस्थिति दर कोई बेहतर नहीं है, केवल 7% स्कूल ही 50% से अधिक विद्यार्थियों की उपस्थिति का दावा करते हैं। लेकिन सैंपल के आधे से अधिक उच्च-प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 8 शिक्षक थे, और लगभग 81% ने दावा किया कि उनके पास पर्याप्त मध्याह्न भोजन निधि थी। बुनियादी ढांचे की दृष्टि से, ये स्कूल अपने प्राथमिक समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं, 65% के पास लाइब्रेरी है, 83% के पास खेल मैदान, और 22% के पास बिजली, पानी की आपूर्ति और शौचालय (तीनों) हैं। फिर भी, बहुत कम ही न्यूनतम आरटीई मानदंडों को पूरा करते हैं।

जैसा कि रिपोर्ट कार्ड से पता चलता है, लाखों छोटे बच्चों के लिए इस क्षेत्र के स्कूल संघर्ष के स्थल हैं । मानो शिक्षकों, बुनियादी ढांचे और सरकारी और सामाजिक प्रतिबद्धता की लगातार कमी पर्याप्त नहीं थी, डीबीटी जैसी नीतियां और कोविड से संबंधित स्कूल बंद होने के दौरान और बाद में घटिया प्रयास जले पर नमक छिड़क रहे हैं।

बिहार में स्कूली शिक्षा संकट पर कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं हो रही है । ऐसा इसलिए क्योंकि इस संकट का सबसे ज्यादा असर वंचित समूहों पर पड़ता है. जिनके पास साधन हैं उन्होंने अपना भरोसा निजी स्कूलों, कोचिंग सेंटरों और ट्यूशन पर रखा है और इस प्रकार सार्वजनिक स्कूलों को बेहतर बनाने में उनकी कोई रुचि नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासक स्कूली शिक्षा की स्थिति और गुणवत्ता की तुलना में स्थानान्तरण, खरीद और रिकॉर्ड-रख-रखाव के बारे में अधिक चिंतित हैं। जहां तक नीति निर्माताओं और राजनीतिक नेताओं का सवाल है, प्रारंभिक शिक्षा कोई गर्म विषय नहीं है। इसलिए संकट बरकरार है.

इस संकट को समाप्त करने के लिए तत्काल और बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है। आरटीई, भावना और विशिष्टता दोनों में, ऐसे प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश के रूप में काम कर सकता है। आरटीई का जोर प्रत्येक बच्चे के लिए एक संपूर्ण और सशक्त स्कूल वातावरण के निर्माण पर है । यही उत्तरी बिहार में स्कूली शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अधिनियम में इस उद्देश्य के लिए कई उपयोगी प्रावधान शामिल हैं, जो न केवल स्कूल सुविधाओं से संबंधित हैं, बल्कि न्यूनतम मानदंड, कक्षा घंटे, पाठ्यक्रम विकास, निर्देश भाषाएं, संवैधानिक मूल्य, शिक्षण विधियां, शारीरिक सुरक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, भागीदारी प्रबंधन, अभिभावक-शिक्षक सहयोग, सामाजिक समानता, पूर्वस्कूली शिक्षा और निजी ट्यूशन से भी संबंधित हैं। इन प्रावधानों को समझने और लागू करने से शिक्षा के अधिकार को वास्तविकता बनाने में बहुत मदद मिल सकती है, विशेष रूप से माता-पिता को अधिक मांग करने और प्रणाली को अधिक जवाबदेह बनाने से।

चित्र 12: एक प्राथमिक विद्यालय जिसमें बच्चे बिना गणवेश के बैठे हैं। (श्रेय: प्रियांश सिन्हा और हर्ष राज)

हालाँकि समय के साथ व्यापक कार्रवाई की आवश्यकता है, सर्वेक्षण दो प्राथमिक चिंताओं की ओर इशारा करता है। सबसे पहले, स्कूल में बेहद कम उपस्थिति की समस्या को समझने और उसका समाधान करने की तत्काल आवश्यकता है। हमने विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के चौंकाने वाले स्तर (औसतन दिन में लगभग 80%) के संभावित कारणों पर चर्चा की है, लेकिन उनकी और जांच की आवश्यकता है। इसके लिए माता-पिता और बच्चों के साथ व्यापक चर्चा की आवश्यकता होगी। अन्य संभावित प्रतिक्रियाओं में, मध्याह्न भोजन के साथ सप्ताह में एक बार के बजाय हर दिन अंडे उपलब्ध कराने से मदद मिल सकती है। किसी भी स्थिति में ऐसा करना एक अच्छी बात होगी, जैसा कि कई अन्य राज्य पहले ही मान चुके हैं।

दूसरा, डीबीटी विफलता इस अजीब और अनुचित नीति को तत्काल बदलने की मांग करती है । पाठ्यपुस्तकों और पोशाक के अकुशल वितरण के मुद्दों को संबोधित करने का यह सही तरीका नहीं है। समय पर वितरण कोई रॉकेट विज्ञान नहीं है - कई अन्य राज्यों (सभी दक्षिण भारतीय राज्यों सहित) ने दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। पर्याप्त योजना के साथ, स्कूल वर्ष की शुरुआत में किताबें और पोशाक आसानी से स्कूलों तक पहुंच सकती हैं।

उत्तर बिहार के स्कूली शिक्षा संकट को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास और जिम्मेदारी की आवश्यकता है। जहां राज्य सरकार और प्रशासन की व्यवस्था को ठीक करने की प्राथमिक जिम्मेदारी है, वहीं सामाजिक आंदोलनों और बड़े पैमाने पर समाज को भी सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है। डॉ. अम्बेडकर के नारे "शिक्षित हो, संगठित हो संघर्ष करो" से प्रेरणा लेते हुए, उत्तर बिहार के प्रत्येक बच्चे की शिक्षा के लिए सामूहिक रूप से आंदोलन और संगठित होने का समय आ गया है।

परिशिष्ट तालिकाएँ

तालिका A1: शिक्षकों की संख्या के आधार पर स्कूलों का प्रतिशत वितरण

शिक्षकों की संख्या	प्राथमिक विद्यालय (%)	उच्च-प्राथमिक विद्यालय (%)	सभी सैंपल स्कूल (%)
2	20	0	10
3	25	2	14
4	43	5	23
5 – 8	12	44	28
9-12	0	32	16
13-18	0	17	9

कॉलम टोटल = 100.

तालिका A2: विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर स्कूलों का प्रतिशत वितरण

विद्यार्थियों की संख्या	प्राथमिक विद्यालय (%)	उच्च-प्राथमिक विद्यालय (%)	सभी सैंपल स्कूल (%)
150 से कम	60	0	30
150 – 300	32	22	27
301 - 500	8	43	26
501-800	0	25	12
800 से अधिक	0	10	5

कॉलम टोटल = 100.

परिशिष्ट तालिकाएँ

तालिका A3: लिंग द्वारा शिक्षकों का प्रतिशत वितरण

	प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक (%)	उच्च-प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक (%)
पुरुषों	57	58
महिलाओं	43	42

तालिका A4: सैंपल शिक्षकों की सामाजिक संरचना और बिहार की जनसंख्या (%)

	शिक्षक (प्राथमिक और उच्च-प्राथमिक विद्यालय)	बिहार की जनसंख्या ए
अनुसूचित जाति	17	16
अनुसूचित जनजाति	3	1
अन्य पिछड़ा वर्ग	43	50
मुसलमान	19	17
आम	18	16

ए: जनगणना 2011. ओबीसी और मुस्लिम के लिए इंडिया ह्यूमन डेवलोपमिन्ट सर्वे (2011-12). अंतिम आंकड़ा 100% से घटाकर अनुमान लगाया गया है. कॉलम टोटल = 100.

संदर्भ

1. एएसईआर. (2014)। बिहार प्राथमिक विद्यालय अध्ययन। नई दिल्ली: एएसईआर.
2. घटक, एन., यारेसीमे, एएस, और झा, जे. (2020)। कोविड-19 के समय में जीवन: भारत में स्कूल जाने वाले बच्चों, विशेषकर लड़कियों के जीवन पर कोविड-19 के प्रभाव का मानचित्रण। बेंगलुरु: बजट और नीति अध्ययन केंद्र।
3. ज्ञान विज्ञान समिति, झारखण्ड। (2022)। कक्षा में उदासी. रांची: ज्ञान विज्ञान समिति झारखंड.
4. हिंदू ब्यूरो, टी. (2023, 8 जून)। मध्याह्न भोजन खाने के बाद 150 बच्चों के बीमार पड़ने की घटना पर एनएचआरसी ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। द हिंदू से लिया गया: https://www.thehindu.com/news/national/nhrc-issues-notice-to-the-bihar-government-over-an-incident-of-150-children-falling-ill-after-consuming-midday-meal/article66946873.ece
5. झा, एएन (2023, 29 मई)। बिहार के सुपौल में मिड-डे मील खाने से 25 स्कूली बच्चे बीमार पड़ गये. हिंदुस्तान टाइम्स से लिया गया: https://www.hindustantimes.com/cities/patna-news/25-bihar-schoolchildren-fall-ill-after-eating-mid-day-meal-with-dead-lizard-100-others-fell-sick-due-to-dead-snake-101685363262430.html
6. कुमार, ए. (2022, 16 अक्टूबर)। 5 साल बाद, बिहार छात्रों को किताबें आपूर्ति करने की पुरानी प्रथा पर वापस लौटेगा, लेकिन चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं । हिंदुस्तान टाइम्स से लिया गया: https://www.hindustantimes.com/cities/patna-news/5-yrs-on-bihar-to-revert-to-the-old-practice-of-supplying-books-to-students-but-challenges-remain-101665938861479.html
7. मिश्रा, बी. (2023, 9 जनवरी)। नहीं पर सरकार से जवाब मांगा. बिहार में भूमिहीन विद्यालयों की . टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया: https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/govts-reply-sought-on-no-of-landless-schools/articleshow/96842885.cms
8. स्कूल टीम, टी. (2021)। लॉक्ड आउट: स्कूली शिक्षा पर आपातकालीन रिपोर्ट। रांची: रोड स्कोलर्ज.
9. यूनिसेफ इंडिया, सीओ (2021)। कोविड के संदर्भ में स्कूल बंद होने के दौरान सीखने का त्वरित मूल्यांकन। नई दिल्ली: संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ)